



रिटेलर हो या कस्टमर
**कॉल लगाओ
गाड़ी बुलाओ**



 **1800 120 2727**

सुपरमार्केट चार पहियों पर घर आएगा



**FIXED
PRICE**

- शरबती सुपीरियर आटा
- देशी चक्की आटा
- सूजी
- दलिया
- बेसन
- शरबती गेहूँ
- देशी गेहूँ
- प्लैटिनम शरबती चावल

- एलीट बासमती चावल
- पोहा
- लाकाडोंग हल्दी पाउडर
- मिर्च पाउडर
- धनिया पाउडर
- जीरा
- सौंफ
- चना दाल

- मूंग दाल (छिलका)
- मूंग दाल
- अरहर/तूर दाल
- उड़द दाल (छिलका)
- उड़द दाल
- मसूर मलका
- मसूर दाल
- काला चना

- काबुली चना
- हरा चना
- हरा मटर
- मोठ
- हरा मूंग
- राजमा चित्रा
- राजमा लाल
- राजमा कश्मीरी

- कैलिफोर्निया बादाम
- काजू
- पिस्ता
- किशमिश
- अखरोट
- मामरा बादाम

**COMING
SOON**

- कच्ची घानी सरसों का तेल
- ट्रिपल फ़िल्टर्ड मूंगफली तेल
- तिल का तेल
- मखाना

- खजूर
- अंजीर
- मूंगफली
- लौंग

- इलायची
- काली मिर्च
- दालचीनी
- अजवाइन

- राई
- मेथी दाना
- कसूरी मेथी
- ह्रींग

- अमचूर पाउडर
- गुड़ पाउडर
- चाय और भी बहुत कुछ

**ORDER ON
WEBSITE**



**ORDER ON
WHATSAPP**



**ORDER ON
APP**



AVAILABLE AT

 27000+ RETAILERS

 SUPERMARKETS

 QUICKCOM/ECOM

 WEBSITE

 WHATSAPP

 APP

 TOLL FREE

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। -शेक्सपियर

अरावली में घासभूमियों का पुनर्स्थापन

अरावली पर्वतमाला के घासभूमियाँ या घास के मैदान जैव विविधता एवं आजीविका की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सैकड़ों वनस्पति एवं जीव प्रजातियों का आवास प्रदान करती हैं तथा स्थानीय पशुपालक समुदायों को चारा व आजीविका उपलब्ध कराती हैं। घासभूमियों की पारिस्थितिक सेवाओं में मिट्टी का संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, कार्बन संयंत्रण एवं मरुस्थलीकरण को रोकना शामिल है। एक अध्ययन में राजस्थान की घासभूमियों में 37.5 से अधिक पादप प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जो इन पारिस्थितिकियों की समृद्ध जैव-विविधता दर्शाता है।

इतने महत्व के बावजूद घासभूमियों को नीति एवं प्रबंधन में लम्बे समय तक 'बंजर भूमि' समझने की भूल होती रही है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश हुकूमत ने जिन खुली चरागाह भूमि को वाणिज्यिक वानिकी हेतु अनुपयोगी पाया, उन्हें बंजर घोषित कर दिया था। आजादी के बाद भी यह दृष्टिकोण काफी हद तक बना रहा।

अरावली क्षेत्र की घासभूमियों की परिस्थितियों राज्य के अन्य भागों से भिन्न हैं। अरावली पहाड़ियों में घासभूमियाँ प्रायः खंडित रूप में जंगलों में मिलती हैं। विस्तृत समतल चरागाह अधिकतर पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की घासभूमियाँ अत्यधिक जैव-विविध हैं, और कुछ अरावली से संबद्ध घास के मैदानों में प्रजाति-विविधता सबसे अधिक पाई गई है।

घासभूमियों के क्षरण के अनेक कारण रहे हैं। भूमि-उपयोग परिवर्तन और बढ़ता दबाव एक प्रमुख कारण है - बढ़ती मानव व पशु आबादी ने चरागाहों पर अत्यधिक भार डाल दिया है। कई घासभूमि क्षेत्रों को कृषि, उद्योग या शहरी विकास के लिए बदल दिया गया, और कुछ में खनन व अतिक्रमण से गंभीर क्षति हुई। साथ ही, वर्षों पर फैलित नीतियों ने घासभूमियों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है। हरित आवरण बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे करने के लिए घासभूमि पर वृक्ष लगाना एक आसान तरीका समझा गया।

घासभूमियों में आक्रामक गैर-स्थानिक पौधों का प्रसार एक और बड़ी चुनौती है। राजस्थान और अरावली क्षेत्र में विलायती बबूल एक प्रमुख आक्रामक है जिसे बड़े इलाके में फैले खुले चरागाहों को घने कांटेदार झाड़-झंखाड़ में बदल दिया है। गुजरात के स्थानीय कार्बन बंधार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा संग्रहीत करती है, जिसमें करीब 90 प्रतिशत कार्बन भूमिगत जड़ों एवं मिट्टी में रहता है। अतः घासभूमि बहाली से भारी मात्रा में कार्बन मिट्टी में बंधकर रखने में सहायता मिलेगी, जो एक महत्वपूर्ण जलवायु लाभ है। साथ ही, घासभूमि में प्रजातियों की विविधता बढ़ने से पौधों द्वारा भूमिगत कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्मजीव पदार्थ (मृतजीव द्रव्य) का योगदान बढ़ता है, जिससे मिट्टी में कार्बन स्थायी रूप से जमा होता है। जैव-विविधता की बहाली - विशेषकर तरह-तरह की घासों व चौड़ी पत्ती वाली जड़ी-बूटियों की उपस्थिति - मिट्टी की संरचना सुधार कर जल-धारण क्षमता बढ़ाती है। घने घास आवरण वर्षों के जल को भूमि में सोखकर भू-जल स्तर सुधारता है, मिट्टी कटाव रोकता है तथा सूखे के दौरान भी भूमि को खुली बंजर होने से बचाकर स्थानीय जलवायु को मंद बनाए रखता है।

घासभूमि पुनर्स्थापन की कार्यनीतियों में सबसे पहला कदम आक्रामक वृक्षों को नियंत्रित करना है। शोध से प्रमाण मिला है कि यदि यांत्रिक उपायों से जड़ सहित हटाया जाए तो घासभूमि की देशज वनस्पति तीव्रता से लौटने लगती है। गुजरात के बनी घासभूमि में 4 वर्ष तक हुए एक प्रयोग में विदेशी बबूल को पूरी तरह उखाड़ने वाले भूखंडों में शाकीय प्रजाति विविधता व आवरण नियंत्रण की तुलना में तीन से छह गुणा तक बढ़ गया, जबकि केवल शाखाओं की छंटाई करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। अतः जहाँ संभव हो, प्रोसोपिसा कृष्ण निक्फासन श्रेष्ठ पारिस्थितिक परिणाम देता है। हालाँकि बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर ऐसा करना खर्चीला है और प्रोसोपिस से कुछ स्थानीय लाभ (ईंधन) भी जुड़े हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते की जरूरत है और क्रमिक रूप से हटाया जा सकता है।

पुनर्स्थापन में यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल घास ही नहीं, बल्कि घासभूमि में पाई जाने वाली अन्य देशज जड़ी-बूटियों (फ़ोब्स) भी वापस आएँ। पुरानी घासभूमियों में फ़ोब प्रजातियाँ कुल वनस्पति विविधता का बड़ा हिस्सा होती हैं और पारिस्थितिकी सेवाओं व चारा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये प्रजातियाँ आग, चराई, सूखा व पाला जैसे तनावों को सहाकर घासभूमि की कार्यात्मक विविधता बनाए रखती हैं, फिर भी अब तक घासभूमि प्रबंधन में इनके संरक्षण पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। अतः बहाली योजनाओं में घासों के साथ-साथ महत्वपूर्ण फ़ोब प्रजातियों के बीजों का रोपण व प्रसार पर बल दिया जाए, ताकि संपूर्ण जैव-विविधता लौट सके। यदि कुछ बहुमूल्य

बहुवर्षीय घास या फ़ोब प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पुनरावर्तन में कठिनाई महसूस कर रही हों तो उनकी सक्रिय पुनर्स्थापना (री-इंट्रोडक्शन) के उपाय करने चाहिए। उदाहरण के लिए पुराने सुरक्षित घास के मैदानों से अलग-अलग पट्टियों से ऊपर की 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी लाकर पुनर्स्थापन क्षेत्र में बिखरने से मुदा का सीड-बैंक भी आ जायेगा। ध्यान यह रखना है कि प्राचीन और सुरक्षित घास के क्षेत्रों से मिट्टी पूरी सतह से नहीं बल्कि पट्टियों के रूप में लाई जाए। महाराष्ट्र के अनुभव बताते हैं कि घास की विविध प्रजातियों को पौधशाला में उगाकर पुनर्स्थापन क्षेत्र में रोपित करना भी एक विकल्प है।

घासभूमि पुनर्स्थापन केवल पारिस्थितिकी का नहीं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता का भी विषय है। घासभूमियाँ सदियों से स्थानीय चरागाहों, पशुपालकों और आदिवासी समुदायों की आजीविका का आधार रही हैं, इसलिए इनके पारंपरिक ज्ञान और भागीदारी के बिना पुनरुद्धार सफल नहीं हो सकता। समुदायों को साथ लेकर चलने के लिए भागीदारीपूर्ण तरीके अपनाने होंगे।

बहुवर्षीय घास या फ़ोब प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पुनरावर्तन में कठिनाई महसूस कर रही हों तो उनकी सक्रिय पुनर्स्थापना (री-इंट्रोडक्शन) के उपाय करने चाहिए। उदाहरण के लिए पुराने सुरक्षित घास के मैदानों से अलग-अलग पट्टियों से ऊपर की 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी लाकर पुनर्स्थापन क्षेत्र में बिखरने से मुदा का सीड-बैंक भी आ जायेगा। ध्यान यह रखना है कि प्राचीन और सुरक्षित घास के क्षेत्रों से मिट्टी पूरी सतह से नहीं बल्कि पट्टियों के रूप में लाई जाए। महाराष्ट्र के अनुभव बताते हैं कि घास की विविध प्रजातियों को पौधशाला में उगाकर पुनर्स्थापन क्षेत्र में रोपित करना भी एक विकल्प है।

घासभूमि पुनर्स्थापन केवल पारिस्थितिकी का नहीं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता का भी विषय है। घासभूमियाँ सदियों से स्थानीय चरागाहों, पशुपालकों और आदिवासी समुदायों की आजीविका का आधार रही हैं, इसलिए इनके पारंपरिक ज्ञान और भागीदारी के बिना पुनरुद्धार सफल नहीं हो सकता। समुदायों को साथ लेकर चलने के लिए भागीदारीपूर्ण तरीके अपनाने होंगे। गुजरात के बनी घास के मैदानों में प्रोसोपिस निक्फासन एक विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि प्रोसोपिस ने जहाँ पारिस्थितिकी को बदला है वहीं कुछ लोगों की आय का स्रोत भी बन गया है।

प्रोसोपिस हटाने से चरागाह बढ़कर पशुधन संख्या व दुग्ध उत्पादन आय में लंबे समय में वृद्धि होगी, लेकिन इस पर निर्भर कोयला/ईंधन आय खत्म होने से कुछ परिवारों को वैकल्पिक आजीविका की आवश्यकता पड़ेगी। इन निष्कर्षों से जाहिर है कि घासभूमि पुनर्स्थापन करते समय समुदाय की आजीविका और जोखिम प्रबंधन की योजना साथ-साथ बनानी चाहिए। जिन लोगों पर प्रारंभिक समय में प्रतिकूल असर पड़े, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार/आय के स्रोत विकसित करना और मौसम आपदा की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन करना आवश्यक होगा। स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही ऐसे लाभ-हानि के संतुलन साधे जा सकते हैं।

शासन स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में घासभूमि संरक्षण की जिम्मेदारी कई विभागों में बंटी होने से स्पष्ट नेतृत्व का अभाव है। कुछ घासभूमि क्षेत्र वन विभाग के अधीन हैं, कई चरागाह राजस्व या पंचायती भूमि में हैं, तथा कुछ भूमि को कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत अलग दिशा में उपयोग किया जाता है। इस विभाजित प्रबंधन के कारण घासभूमियाँ उपेक्षित या विरोधाभासी नीतियों का शिकार हो जाती हैं।

जरूरत है एक समेकित नीति की, जिसमें घासभूमियों को एक स्वतंत्र व मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता मिले। सरकार को भाषा में 'बंजर भूमि' शब्दावली को हटाकर इसे बदलने हेतु औपचारिक कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर स्पष्ट रूप से घासभूमि संरक्षण व पुनरुद्धार के लक्ष्य निर्धारित हों। वन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्यों में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राकृतिक घासभूमियों को वृक्षारोपण से आच्छादित करने की गलती न हो। घासभूमि प्रबंधन में नियंत्रित आग एवं नियंत्रित चराई जैसे पारंपरिक तरीकों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्हें प्रक्रियाओं ने कई घासभूमियों को सहस्राब्दियों तक बनाए रखा है। प्राण-स्तर पर परंपरागत चरागाह प्रबंधन (जैसे चौमासा बंदी, चरबद्ध चराई, आदि) के अनुभवों को भी आधुनिक योजनाओं में समाहित करना उचित होगा। पुनरुद्धार कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को रोजगार और निर्णय-निर्धारण भूमिकाओं में सम्मिलित करना उचित होगा। पुनरुद्धार कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को रोजगार और निर्णय-निर्धारण भूमिकाओं में सम्मिलित करना उचित होगा। पुनरुद्धार कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को रोजगार और निर्णय-निर्धारण भूमिकाओं में सम्मिलित करना उचित होगा।

अरावली क्षेत्र के संदर्भ में पुनर्स्थापन करते समय कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ वर्षा अत्यधिक अनियत है - कभी अत्यल्प तो कभी अतिशय - इसलिए ऐसे देशज घास एवं फ़ोब प्रजातियों का मिश्रण रोपित करना होगा जो सूखे व अति-वर्षा दोनों परिस्थितियों में टिक सके। खारे व दलदली स्थलों के लिए विशिष्ट सहनशील प्रजातियों का चयन करना होगा - जैसे सांभर की खारी भूमि में स्यूडा जैसी लवण-सहिष्णु झाड़ी। ताकि ये कठिन परिस्थितियों में भी पनपें। अरावली की दलानों पर मिट्टी कटाव रोकने हेतु पुनरुद्धार के साथ कंटूर बांध, पत्थर कतार आदि संरक्षण उपाय करने चाहिए ताकि नई घासों की जड़ें मजबूत हो सकें। प्रारंभिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित चरागाह क्षेत्रों को अत्यधिक चराई से बचाने के लिए कुछ समय तक संरक्षण देना पड़ेगा; समुदाय की सहमति से अस्थायी घेराबंदी कर पौध स्थापित करें, फिर चरणबद्ध ढंग से नियंत्रित चराई की अनुमति दें ताकि चरागाह और पशुधन दोनों टिकाऊ रहें।

निष्कर्षतः अरावली क्षेत्र में घासभूमि पुनरुद्धार एक बहुआयामी अभियान है, जो पारिस्थितिकी, समाज और शासन - तीनों के समन्वित प्रयास से ही सफल होगा। शोध स्पष्ट करते हैं कि घासभूमियाँ 'बंजर' नहीं बल्कि समृद्ध और प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनके बहाली से जलवायु अनुकूलन व शमन, जैव-विविधता संरक्षण और समुदायों की आजीविका - तीनों उद्देश्यों में लाभ होगा। हाल ही में इस विषय पर तकनीकी जानकारी साझा करने हेतु वन विभाग राजस्थान और द नेचर कंसेर्वेंसी (टीएनसी) द्वारा अरावली के जिलों में कार्य करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों हेतु एक कार्यशाला आयोजित हो रही है। आशा की जाती है कि इससे अरावली में लगभग 35,000 हेक्टेयर घास के मैदानों के पुनर्स्थापन हेतु उपयोगी जानकारी का आदान-प्रदान होगा।

-अतिथि संपादक, डॉ. दीप नारायण पाण्डेय (इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर) (यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में बदलता हुआ शिक्षा का परिदृश्य: राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका



अशोक कुमार

आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केवल विज्ञान कथाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। शिक्षा का क्षेत्र भी इस क्रांति से अछूता नहीं है। एआई के आगमन ने ज्ञान के प्रसार, सीखने के तरीकों और शैक्षिक सामग्री के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया है। इस बदलते परिदृश्य में, शिक्षण संस्थानों की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रह गई है; उन्हें अब भावी राष्ट्र निर्माताओं को इस एआई-चालित दुनिया के लिए तैयार करने की महती जिम्मेदारी निभानी है। राष्ट्र निर्माण का कार्य इंटर, पत्थर और स्टील से नहीं, बल्कि सशक्त, कुशल और नैतिक रूप से जागरूक मानव संसाधन से होता है, और यही वह धुरी है जिस पर शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व टिका है।

एआई द्वारा शिक्षा में लागू एक प्रमुख परिवर्तन एआई ने शिक्षा के पारंपरिक मॉडल में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं: - वैयक्तिकृत शिक्षण एआई-आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म छात्र के सीखने

की गति, क्षमता और रुचियों का विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण प्रत्येक छात्र के लिए एक अनुकूलित पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री तैयार करने में मदद करता है। यह एक ही आकार सभी के लिए वाले पारंपरिक मॉडल से हटकर प्रत्येक छात्र के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह वैयक्तिकरण सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आनंददायक बनाता है।

स्मार्ट कंटेंट और एक्सप्लेनेबिलिटी : एआई पाठ्यपुस्तकों और वीडियो को इंटरैक्टिव (संवादात्मक) और अनुकूली सामग्री में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी विशेष अवधारणा को समझने में संघर्ष करता है, तो एआई स्वचालित रूप से अतिरिक्त उदाहरण, सिमुलेशन या अलग-अलग स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। इससे ज्ञान की उपलब्धता बढ़ती है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों और दिव्यांग छात्रों के लिए।

प्रशासनिक और मूल्यांकन दक्षता : शिक्षक का अधिकांश समय मूल्यांकन, ग्रेडिंग और प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत होता है। एआई-संचालित उपकरण इन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की जाँच करना या निबंधों का प्रारंभिक मूल्यांकन करना। इससे शिक्षकों को छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने और रचनात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है।

नए कौशल की मांग : एआई के उदय ने कई पुरानी नौकरियों को अप्रचलित कर दिया है और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रॉप्ट इंजीनियरिंग, एआई एथिक्स जैसे नए क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। शिक्षण संस्थानों को अब इन भविष्य के कौशलों को अपने पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाना होगा। राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की केंद्रीय भूमिका एआई के इस नए युग में शिक्षण संस्थानों की भूमिका केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करने से नहीं अधिक व्यापक है। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुआयामी हैं:

21 वीं सदी के कौशल का विकास : एआई दोहराए जाने वाले और डेटा-आधारित कार्यों को संभाल लेगा। इसलिए, छात्रों को ऐसे उच्च-स्तरीय मानवीय कौशल सिखाने की आवश्यकता है जिन्हें एआई आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: आलोचनात्मक चिंतन : एआई द्वारा उत्पन्न जानकारी का मूल्यांकन और विश्लेषण करना।

समस्या-समाधान: जटिल, वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान विकसित करना। रचनात्मकता और नवाचार: नए विचारों को जन्म देना और नवाचार को बढ़ावा देना।

एआई साक्षरता और नैतिक शिक्षा : शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र न केवल एआई का उपयोग करना सीखें, बल्कि यह भी समझें कि यह कैसे काम करता है। इससे भी महत्वपूर्ण, उन्हें एआई के नैतिक पहलुओं के बारे में शिक्षित करना होगा। डेटा प्राइवसी, पूर्वाग्रह और एआई

के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य है। एक नैतिक रूप से जागरूक एआई-कुशल कार्यबल ही एक न्यायसंगत और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करेगा। अनुसंधान और नवाचार केंद्र : विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को एआई उपकरणों को अब इन भविष्य के कौशलों को अपने पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाना होगा। राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की केंद्रीय भूमिका एआई के इस नए युग में शिक्षण संस्थानों की भूमिका केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करने से नहीं अधिक व्यापक है। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुआयामी हैं:

21 वीं सदी के कौशल का विकास : एआई दोहराए जाने वाले और डेटा-आधारित कार्यों को संभाल लेगा। इसलिए, छात्रों को ऐसे उच्च-स्तरीय मानवीय कौशल सिखाने की आवश्यकता है जिन्हें एआई आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: आलोचनात्मक चिंतन : एआई द्वारा उत्पन्न जानकारी का मूल्यांकन और विश्लेषण करना।

समस्या-समाधान: जटिल, वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान विकसित करना। रचनात्मकता और नवाचार: नए विचारों को जन्म देना और नवाचार को बढ़ावा देना।

एआई साक्षरता और नैतिक शिक्षा : शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र न केवल एआई का उपयोग करना सीखें, बल्कि यह भी समझें कि यह कैसे काम करता है। इससे भी महत्वपूर्ण, उन्हें एआई के नैतिक पहलुओं के बारे में शिक्षित करना होगा। डेटा प्राइवसी, पूर्वाग्रह और एआई

के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य है। एक नैतिक रूप से जागरूक एआई-कुशल कार्यबल ही एक न्यायसंगत और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करेगा। अनुसंधान और नवाचार केंद्र : विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को एआई उपकरणों को अब इन भविष्य के कौशलों को अपने पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाना होगा। राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की केंद्रीय भूमिका एआई के इस नए युग में शिक्षण संस्थानों की भूमिका केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करने से नहीं अधिक व्यापक है। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुआयामी हैं:

25 दिसंबर को जयपुर में एमएनआईटी द्वारा किया जाएगा सम्मानित

माला निर्माण जैसे स्वरोजगार आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत कर हज़ारों युवक-युवतियों को आजीविका से जोड़ा गुप्ता के सतत एवं व्यक्तिगत प्रयासों का ही परिणाम है कि भरतपुर में देश की सबसे बड़ी शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना संभव हो सकी। इसके माध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

कृषि चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं: डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम में निहित पूर्वाग्रह (जो सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है), और उच्च-गुणवत्ता वाले एआई उपकरणों की लागत।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षण संस्थानों को: बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। एआई साक्षरता को प्रारंभिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। निरंतर कौशल अद्ययन को एक संस्थागत संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहिए। मानवीय मूल्यों और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को और मजबूत करना चाहिए, ताकि तकनीकी प्रगति मानवीय दृष्टिकोण से संतुलित रहे।

निष्कर्ष - एआई का युग शिक्षा के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व अवसर है। शिक्षण संस्थान अब केवल डिग्रियाँ देने वाली फैक्ट्री नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के वह शक्तिशाली इंजन हैं जो मानव पूंजी को एआई की शक्ति से लैस कर रहे हैं। उन्हें अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों और नैतिक ढांचे में क्रांति लानी होगी। एआई के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा करना सीखने वाला एक सशक्त, नैतिक और कुशल युवा ही 21 वीं सदी में भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं है; यह एक सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन है जिसकी अगुवाई शिक्षण संस्थानों को करनी होगी।

-अशोक कुमार, पूर्ण कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक विस्तारित हुआ। वर्तमान में इस व्यवसाय से लगभग 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और करीब 9 हजार मेट्रिक टन शहद का विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसी कारण भरतपुर को 'शहद का

मध्यम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय न केवल भरतपुर बल्कि राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों के साथ-साथ मध्यप्र

क्या भाजपा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को बैलेंस कर लेगा पंकज चौधरी को यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर?

भाजपा अब हर राजनीतिक निर्णय यू.पी. में वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखकर ले रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले को राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सोच-समझकर दिया गया संकेत और राज्य के लिए केन्द्रीय नेतृत्व की दीर्घकालिक चुनावी च संगठनात्मक योजना का हिस्सा माना जा रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि यह कदम इस बात को रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति को काफी पहले से आकार देने को लेकर दृढ़ हैं, और योगी आदित्यनाथ को समय से पहले पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है।

उन्के अनुसार, यह नियुक्ति देश के सबसे अहम चुनावी राज्य में "सत्ता-केन्द्रों के पुनर्संतुलन" को साधने का

- क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, जितना भाजपा आशा कर रही थी। इन नतीजों के कारण ही केन्द्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को अन्य सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा था।
- अब भाजपा अगले चुनाव में उस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहती है।

एक सोच-समझा प्रयास है।

उत्तर प्रदेश से सात बार सांसद रहे और प्रभावशाली कुर्मी समुदाय के प्रमुख नेता पंकज चौधरी के पास संगठनात्मक अनुभव के साथ-साथ, मजबूत सामाजिक आधार भी है। उनकी पदोन्नति को ऐसे समय में गैर-यादव ओबीसी समर्थन को मजबूत करने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाकर अपने सामाजिक गठजोड़ को विस्तार देने की

कोशिश कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पंकज चौधरी को योगी आदित्यनाथ के निकटवर्ती राजनैतिक गुट का हिस्सा नहीं माना जाता। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उनके चयन का यही एक अहम कारण था। केन्द्रीय नेतृत्व योगी की उन जानी-पहचानी असहजताओं को भी ध्यान में रखे हुए था, जो उन्हें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं से रहती हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पकड़ है। चौधरी को चुनकर पार्टी ने ऐसा चेहरा चुना है, जो दिल्ली को स्वीकार्य है,

लेकिन मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सत्ता के लिए चुनौती भी नहीं है। पर्यवेक्षक इसमें पूर्वी भारत से जुड़ी एक व्यापक रणनीति भी देख रहे हैं। कुर्मी फैक्टर न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि पड़ोसी बिहार में भी अहम है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस समुदाय पर अब भी काफी प्रभाव है। भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि चौधरी की नियुक्ति से नीतीश के उस प्रभाव को कम किया जा सकता है और इस प्रकार बिहार में पार्टी की रणनीति के साथ यूपी के पूर्वी जिलों का बेहतर तालमेल में बिठाया जा सकता है।

राज्य की राजनीति से आगे, इस कदम को मोदी-दौर के बाद, भाजपा में उनके उत्तराधिकार को लेकर चल रही आंतरिक हलचल के बड़े संदर्भ में भी देखा जा रहा है। फिलहाल, शीर्ष नेतृत्व का संदेश साफ है: उत्तर प्रदेश भाजपा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के केन्द्र में रहेगा, और हर संगठनात्मक फैसला 2027, और उसके आगे के समय को पूरी तरह ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष बने

लखनऊ, 13 दिसंबर। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष पद के लिये एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। चौधरी के अध्यक्ष पद पर चुने जाने का औपचारिक ऐलान रविवार दोपहर किये जाने की संभावना है। वह निर्वतमान प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर सिंह चौधरी का स्थान लेंगे।

चौधरी अध्यक्ष पद के इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चार सेट में इस पद के लिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने।

अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर सिंह चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, चौधरी के नामांकन पत्रों में प्रस्तावक बने। चौधरी ने प्रस्तावकों की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और विनोद तावड़े को नामांकन पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले चौधरी का इस पद पर चुना जाना तय है, जिसकी औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर को की जाएगी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज सोनिया गांधी कर्नाटक के मु.मंत्री के पद की गुत्थी पर अपना निर्णय देंगी?

रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस की विशाल रैली के बाद मु.मंत्री सिद्धारमैया व उनके प्रतिद्वंदी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सोनिया गांधी से मिलेंगे

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 दिसंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 14 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। सूत्रों ने बताया, इस बैठक का संबंध कर्नाटक में राज्य के शीर्ष पद को लेकर जारी नेतृत्व विवाद से हो सकता है।

यह बैठक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली कांग्रेस की मेगा रैली के तुरंत बाद तय की गई है। यह रैली पार्टी के "बोट चोर, गद्दी छोड़" अभियान का हिस्सा है। इस अभियान से परिचित लोगों ने बताया कि इसमें भाजपा और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया गया है।

यह प्रकरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के कुछ हफ्तों बाद पुनः सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो "भ्रम" व्याप्त है, उसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वे खुद मिलकर

- कुछ समय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था कि मु.मंत्री पद सिद्धारमैया व शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के लिए बांटा जाएगा। अतः अब अगर शिवकुमार को ढाई साल बाद मु.मंत्री नहीं बनाया गया तो उनकी (खड़गे की) विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी।

- पार्टी के विधायकों में भी चर्चा जोरों से चल रही है कि शिवकुमार शीघ्र ही मु.मंत्री पद की शपथ लेंगे, विधानसभा का वर्तमान सत्र समाप्त होते ही।

सुलझाएंगे। खड़गे के इस बयान से इस मामले में उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की संभावना के संकेत मिले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री पद को साझा करने का समझौता उनके सामने हुआ था, इसलिए यदि शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी।

इस बीच, कर्नाटक कांग्रेस में नई अटकलें सामने आई हैं, क्योंकि नेतृत्व विवाद की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक पार्टी विधायक ने खुले

तौर पर दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी सत्र के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन टिप्पणियों ने सत्ताधारी पार्टी के भीतर पहले से ही संवेदनशील हो चुके इस मुद्दे को फिर से खड़ा कर दिया है।

रामनगर के कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने शुरुवार को सुर्वण विधान सभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह दावा किया था। उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनरेगा हुआ खत्म, उसकी जगह आएगी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार अगले सप्ताह यह बिल लाना चाहती है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 दिसंबर। मनरेगा हुआ खत्म और अब उसकी जगह "पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी" (पीबीजीआरजी) योजना लायी जा रही है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए कानून को मंजूरी दी है, जिसमें प्रत्येक घराने को 100 कार्यदिवसों की बजाय 125 कार्यदिवसों की गारंटी दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार अगले सप्ताह लोकसभा में पीबीजीआरजी बिल पेश करना चाहती है। इस योजना में केन्द्र की हिस्सेदारी 95,600 करोड़ निर्धारित की गई है।

मनरेगा में इस बदलाव का एक स्पष्ट राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में

- 95,600 करोड़ की इस योजना में प्रत्येक परिवार को 100 की जगह 125 कार्य दिवस की रोजगार गारंटी दी जाएगी।

- इस बदलाव के राजनीतिक पहलू भी हैं, जिसमें प्रमुख हैं, पश्चिम बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा से केन्द्र सरकार पर मनरेगा का फंड नहीं देने का आरोप लगाती रही है, वहीं केन्द्र सरकार का आरोप है कि तृणमूल सरकार मनरेगा फंड में गड़बड़ी कर रही है।

- 14-लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक पहलू है, मनरेगा पर कांग्रेस का दावा। कांग्रेस से यह क्रेडिट छीनने के लिए केन्द्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदल दिया, बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा दिया है।

विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस शैल जैन इंडिगो केस की सुनवाई नहीं करेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 दिसंबर। इंटरनेट एक्जिक्शन लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करती है, ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है,

- जस्टिस शैल जैन ने खंडपीठ से नाम वापस ले लिया, जो इंडिगो केस की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि जस्टिस जैन का बेटा इंडिगो में पायलट है।

जिसमें उसने विमान के इंजन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के रूप में अदा किये गये 900 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की मांग की है। ये इंजन और पार्ट्स विदेश में मरम्मत के बाद फिर से भारत में आयात किए गए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मोटी तन्ख्वाह के बावजूद भी पायलट कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं'

दिल्ली हाई कोर्ट ने किंग एयरवेज़ की अपील खारिज कर करते हुए कहा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 दिसंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एयरलाइन पायलट, जिसमें पायलट-इन-कमांड भी शामिल हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा में आते हैं। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उनकी भूमिका तकनीकी और संचालनात्मक रूप से विमान उड़ाने से संबंधित है, न कि प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी कार्य से।

कोर्ट ने पाया कि पदनाम, उड़ानों के दौरान कमांड की जिम्मेदारियाँ, या उच्च वेतन पायलटों को श्रम कानून सुरक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैश्यायन शंकर को खंडपीठ ने किंग एयरवेज़ द्वारा अपने पूर्व पायलटों, जिनमें कप्तान प्रीतम सिंह, मंजीत सिंह और एनडी कथूरिया शामिल थे, के खिलाफ दायर की गई लैटर्स पेटरंट अपील का निपटारा करते हुए यह निर्णय दिया।

- एयरलाइन ने अपनी अपील में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पायलटों को रूका हुआ वेतन देने, अतिरिक्त फ्लाइट आवर्स के लिए विशेष भत्ता व अन्य भुगतान देने के आदेश दिए थे।

- किंग एयरवेज़ ने इस आदेश के विरुद्ध अपील में कहा कि पायलट को बहुत अच्छा वेतन मिलता है और वह फ्लाइट का इंचार्ज होता है और पर्यवेक्षण करता है।

- पर, अदालत ने अपील खारिज कर दी और कहा, पायलट का कू पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और इंडस्ट्रियल डिस्क्यूट एक्ट के तहत वह "कर्मचारी" की श्रेणी में आता है।

एयरलाइन ने पहले के आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें पायलटों को रूका हुआ वेतन देने, अतिरिक्त उड़ान घंटों के लिए इन्सैटिव और संबंधित बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया था कि "कर्तव्यों की प्रमुख प्रकृति" का परीक्षण ही निर्णायक होगा। कोर्ट ने कहा कि हालांकि एक

पायलट-इन-कमांड को सिद्धांत रूप में उड़ान का प्रभारी माना जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह साबित हुआ कि पायलट कू के ऊपर औद्योगिक या प्रशासनिक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षीय या प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं। खंडपीठ ने यह माना कि उनका मुख्य कार्य विमान को चलाने का तकनीकी और कुशल कार्य है।

कोर्ट ने एयरलाइन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पायलट "कर्मचारी" की परिभाषा से बाहर हैं क्योंकि उनका वेतन बहुत अधिक है या उन्हें वरिष्ठ कमांडर के रूप में नामित किया गया है, कोर्ट ने कहा कि वेतन का स्तर केवल तभी प्रासंगिक होता है जब यह साबित किया जाए कि कर्मचारी वास्तव में पर्यवेक्षण का काम कर रहा है।

यदि यह प्रमाण नहीं मिलता कि पायलट वास्तव में पर्यवेक्षीय कार्य कर रहे हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) (चार) के तहत उन्हें कर्मचारी के दायरे से बाहर किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

खंडपीठ ने किंग एयरवेज़ द्वारा विमानन नियमों और अतिरिक्त संचालन मैनुअल्स पर निर्भरता की भी जांच की, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि पायलट कू के सदस्य का पर्यवेक्षण करते हैं। कोर्ट ने कहा कि विमानन नियमों में कोई भी पर्यवेक्षण उड़ान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपने गढ़ में कांग्रेस की हार पर भाजपा को बधाई दी थरूर ने

तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मिजाज बीते कुछ वक्त से बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। पार्टी

- केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में थरूर के क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में भाजपा को अच्छी सफलता मिली है, जबकि कांग्रेस हार गई।

आलाकामान की बैठकों से दूरी और भाजपा से नजदीकी इस बात की तस्दीक है कि थरूर के मन के अंदर कुछ तो चल रहा है। एक दिन पहले जहां उन्होंने कोलकाता के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ग्राम पंचायतों के मुख्यालय क्यों बदले'

जयपुर, 13 दिसंबर (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के मुख्यालयों को बदलने से जुड़े अलग-अलग मामलों में राज्य सरकार और टोंक, धौलपुर व करौली जिलों के कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजित सिंह और जस्टिस रवि

- हाई कोर्ट ने टोंक सरकार तथा राज्य, धौलपुर, करौली कलेक्टरों से जवाब मांगा।

चिरनिया की खंडपीठ ने यह आदेश करौली जिले की ग्राम पंचायत सेंगरपुरा, टोंक जिले की ग्राम पंचायत चावड़िया के अर्जुन लाल और धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत चितौरा के मुन्ना लाल शर्मा की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 दिसंबर। बंटवारे के लगभग आठ दशक बाद, जिसने उपमहाद्वीप भूगोल और स्मृतियों दोनों के बांट दिया था, एक अप्रत्याशित भाषा ने पाकिस्तान के एक क्लासरूम में वापसी की है। संस्कृत, जिसे लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच सभ्यतागत सीमा माना जाता रहा है, को लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में औपचारिक रूप से पढ़ाया जाना शुरू किया गया है। यह कदम इस बात का शांत, लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि पाकिस्तान अब अपने गहरे बौद्धिक अतीत से नए सिरे से जुड़ने की शुरुआत कर रहा है।

- 1947 से, भारत का तर्क था कि कश्मीर, सांस्कृतिक इतिहास व पहचान के कारण भारत का हिस्सा है तथा दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर को मुस्लिम पहचान की दृष्टि से देखता रहा है।

- पर, अब संस्कृत के शैक्षणिक जगत में प्रवेश से पाकिस्तान की इस सख्त सोच में तब्दीली होती नज़र आ रही है।

- क्या यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब कश्मीर को, केवल एक इस्लामिक पहचान के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि एक ऐसी सभ्यता के रूप में देखना शुरू होगा जिस पर कई सदियों से कई सभ्यताओं का असर रहा है।

जीवित रहती हैं।

सोमित अर्थों में देखें तो यह एक

सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सरस डेयरी अध्यक्ष चौधरी दिल्ली रवाना

यह दल रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली में शामिल होगा

अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे व अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की प्रेरणा से कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष गीता चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ता का दल शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। यह दल रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में रैली व इसके बाद आयोजित बोट चोर गद्दी छोड़ सभा में यह सभा भी शिरकत करेंगे। चौधरी ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इसमें पहुंचने का आह्वान किया है। चौधरी ने एक बयान जारी करके कहा कि सैकड़ों महिलाओं के साथ व अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता भी इस सभा में शिरकत करेंगे। विभिन्न चौपहिया वाहनों और बसों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चौधरी के साथ गीता चौधरी कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष, मूलो देवी पूर्व पार्षद, सीमा चौधरी वरिष्ठ सदस्य, निमला डांगी उपाध्यक्ष, विमलेश चौधरी उपाध्यक्ष, सीमा चौपडा उपाध्यक्ष, सीमा व्यास उपाध्यक्ष, अनिता गुप्ता महामंत्री, सुनीता सोनी सचिव, मदीना बानो सचिव, हंजा देवी गुर्जर सचिव, सरोज कंवर ब्लाक अध्यक्ष भिनाय, हंजा देवी



अजमेर कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष गीता चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ता का दल शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ ।

■ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 2 बस व 15 छोटी गाड़ियों से कांग्रेसजन दिल्ली रवाना

नेतड़ ब्लाक अध्यक्ष अराई, लाजवंती डांगी ब्लॉक अध्यक्ष पोसांगन, मीनाक्षी मीणा ब्लाक अध्यक्ष पुष्कर, धीरज खींची ब्लाक अध्यक्ष सरवाड, संतोष भीचर ब्लाक अध्यक्ष रूपनगढ़, रिया सिंह चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष केकडी, चान्दाबाई माली सदस्य, कंचन देवी सदस्य, सायनी बाई सदस्य, रमती बाई सदस्य आदि मौजूद हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 दिसम्बर रविवार को

रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित बोट चोर - गद्दी छोड़ रैली में अजमेर उत्तर के कांटेसजन 2 बस व 15 छोटी गाड़ियों से अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल व आर टी डी सी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश राठौड़ के नेतृत्व में शामिल होने के लिए सभी कांग्रेसजन 13 दिसम्बर शनिवार को रात्रि में 9 बजे अजमेर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ

राजकुमार जयपाल के निवास स्थान से रवाना हुए हैं। धर्मेश राठौड़ के साथ रैली के संबंध में चर्चा करने वाले कांग्रेसजनों में अजमेर उत्तर के ब्लॉक कांटेस पूर्व पार्षद अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व वाहिद मोहम्मद, पार्षद नौरत गुजर, पूर्व पार्षद सर्वेश पारीक व हेमंत जोधा, ब्लॉक सांगटन महासचिव आरिफ खान व विकास चौहान, युनुस शेख, राजेश गोडीवाल, शहनाज आलम, सुवालाल बैरवा, विश्वेश पारीक, निमल पारीक व तनवीर गुर्जर आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे।

विकसित राजस्थान रथ यात्रा महकला से रवाना

गंगापुर सिटी । प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सुशासन की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा महकला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर से शुरू हुई। रथ को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के नेतृत्व में रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी संजय नरुका को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के सार में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि श्विकसित राजस्थान रथ यात्रा सरकार की विकासपरक नीतियों और पारदर्शी प्रशासन को जनता तक पहुंचाने का एक

■ प्रदेश सरकार की योजनाओं का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाएंगे

प्रभावी माध्यम बनेगी। विकास अधिकारी जगदीश गुर्जर ने पारदर्शी शासन और योजनाओं की जन-ऑडिट की सराहना की। जिला प्रभारी संजय नरुका ने सरकार द्वारा घोषणापत्र की अधिकांश उपलब्धियां हासिल करने का उल्लेख किया, जबकि विधानसभा प्रभारी हेमेश्वर वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। पंचायत समिति प्रधान मंजू गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत महकला के सरपंच लखन सेनी ने अतिथियों का माला और दुग्ध पहनकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य दलित और वंचित वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करना था। केंद्र के जिला सह-समन्वयक मनोज कुमार ने दलित अधिकार केंद्र की गतिविधियों का परिचय दिया।

सिंघल, उदय सिंह गुर्जर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनीता वैष्णव, मोर्चा संयोजक जमनालाल वैष्णव, शहर मंडल अध्यक्ष मिथलेश व्यास, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नागेश लोदी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। इसी क्रम में नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान थीम पर एक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्कृत स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताएं हुईं। विद्यार्थियों को गोला व सूखा कचरा अलग-अलग रखने की जानकारी दी गई और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।

फायरिंग का आरोपी पकड़ा

गंगापुर सिटी । मालगोदाम रोड स्थित पुरानी थोक सब्जी मंडी में 2 दिसंबर को दिनदहाड़े हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसटी गंगापुर सिटी टीम के सहयोग से 5000 रुपए के इनामी बदमाश पृथ्वीराज उर्फ प्रिंस उर्फ नंदू गुर्जर (24) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी को जयपुर के शिवदासपुरा से दबोचा गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 2 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी। तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सब्जी मंडी पहुंचे और काढ़ पहलवान उर्फ महेश पर ताबडतोड़ फायरिंग कर दी।

इस हमले में कालू पहलवान को तीन गोलियां लगीं, जबकि एक अन्य दुकानदार भी घायल हो गया। दोनों व्यक्ति को तुरंत गंगापुर सिटी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर लिया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फायरिंग की वजह कृष्णा गुर्जर गैंग और पृथ्वीराज उर्फ प्रिंस उर्फ नंदू गुर्जर गैंग के बीच चल रही पुरानी रंजिश थी।

अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

अजमेर । जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांगलियावास थाना क्षेत्र में एनएच-48 स्थित एक होटल पर छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 115 कमर्शियल गैस सिलेंडर, एक घरेलू सिलेंडर, एक गैस टैंकर तथा चार वाहन जब्त किए हैं। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात की गई। सहायक पुलिस अधीक्षक किरणगढ़ शहर अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी सत्यवान मीणा और उनकी टीम ने केसरपुरा क्षेत्र में स्थित एक पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी। तलाशी के दौरान होटल परिसर में गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त उपकरण मिले, जिससे अवैध रूप से गैस भरने और भंडारण की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके से दो पिकअप वाहन, एक गैस टैंकर और एक लॉडिंग टैंपो जब्त किया।

इसके साथ ही 115 कमर्शियल सिलेंडर और एक घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। एक पिकअप वाहन में डीजल भी पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने केसरपुरा निवासी जितेंद्र कुमार और ठामा मकेंडा निवासी बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सूचना रसद विभाग को भी दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बड़े गैस रिफिलिंग नेटवर्क, सप्लाय चैन और गैस की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है। जांच गहनता से जारी है।

विजय नगर में अवैध खनिज परिवहन करते 4 डंपर जब्त



माईस विभाग की अजमेर वृत्त की टीम ने विजय नगर-नसीराबाद क्षेत्र में देर रात व प्रातः अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ औचक कार्रवाई करते हुए चार डंपर जब्त किये ।

अजमेर/जयपुर । माईस विभाग की अजमेर वृत्त की टीम ने विजय नगर-नसीराबाद क्षेत्र में देर रात व प्रातः अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ एक स्काॅर्पियों कार की मदद से भगा ले जाने में सफल हो गए।

अजमेर वृत्त के अधीक्षण खनि अभियंता जय गुरुबखानी ने बताया कि शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए देर रात विजय नगर और नसीराबाद क्षेत्र में औचक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विजय नगर क्षेत्र में बजरी का अवैध परिवहन करते हुए दो डंपर जब्त किये गये। इसके साथ ही विजयनगर नसीराबाद क्षेत्र में दो

- एस्कोर्ट करती स्काॅर्पियों व संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज
- खान विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा रेत का अवैध परिवहन करते एक डंपर का पीछा करने पर डंपर चालक ने रेत का बीच रोड ही फैलाते हुए फरार हो गया। रेत डंपर का पीछा करती विभागीय टीम के कार्य में एक स्काॅर्पियों से रास्ता रोकने और रेत के डंपर को भगाने में सहयोग किया।

अधीक्षण खनिज अभियंता जय गुरुबखानी ने बताया कि विभागीय टीम के साथ ही खनिज अभियंता विजिलेंस अजमेर, सहायक खनिज अभियंता सावर शामिल रहे। उन्होंने बताया कि रेत का अवैध परिवहन कर भगाने में सफल डंपर चालक, मालिकों और एस्कोर्ट करती स्काॅर्पियों सवारों के खिलाफ पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

डंपर प्रेनाइट का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किये गये हैं।

अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान ही सुशासन का ध्येय : बेढम

- सेऊ-सुहेरा, धमारी और नाहरा चौथ सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में जनसभाओं को संबोधित किया
- जनसुनवाई कर मौके पर ही समस्याओं को निस्तारण

गीत गाते हुए भव्य शकलश यात्रा श्र निकालकर उनका आत्मीय स्वागत किया। पारंपरिक साफे पहना कर और पुष्प वर्षा के साथ ठामोणी ने अपने लाडले मंत्रों का अभिनंदन किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान ने विकास की नई इबारत लिखी है। उन्होंने कहा हमारी सरकार तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण के मंत्र पर काम करती है।

आज श्विकास रथश्र के माध्यम से जो फिल्म दिखाई जा रही है, वह महज प्रचार नहीं, बल्कि उन लाखों लाभार्थियों की हकीकत है जिनके जीवन में उजाला आया है। उन्होंने विशेष रूप से ईआरसीपी (राम जल सेतु), कानून व्यवस्था में सुधार और गोपालन विभाग द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का जिक्र किया। मंत्री बेढम ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना सरकार की शीर्ष

प्राथमिकता है। अपने दौरे के दौरान मंत्री बेढम ने विकास रथ का अवलोकन किया। रथ की बड़ी स्त्रीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेशों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की लघु फिल्मों का प्रसारण देख ठामोणी मंत्रमुग्ध हो गए। अपने दौरे के दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने न केवल सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बल्कि आमजन की समस्याएं भी सुनीं। विजली, पानी और सड़कों से जुड़ी परिवेदनाओं पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए।

इस जनसंपर्क अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

बदनोर के तीन गांवों से डीपी चोरी

भीलवाड़ा। बदनोर पुलिस थाना क्षेत्र में चोरों के हासले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने क्षेत्र के तीन गांवों को निशाना बनाते हुए बिजली के ट्रांसफॉर्मर (डीपी) चोरी कर लिए। डीपी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसका फुटेज सामने आया है।

डीपी चोरी होने से संबंधित गांवों में पूरी रात अंधेरा छाया रहा, जिससे ठामोणी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जुलाई से दिसंबर के साढ़े पांच माह के अंतराल में बदनोर क्षेत्र की 10 पंचायतों में कुल 26 ट्रांसफॉर्मरों से पंचायत व आंखल चोरी हो चुका है। वहीं पिछले करीब ढाई

वर्षों में चोर सरकारी विद्यालयों, अस्पतालों और ठामोणी के घरों को भी निशाना बना चुके हैं। विद्युत निगम की ओर से इस संबंध में बदनोर खाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मोगर पंचायत के बिच्छुदंडा निवासी गोपी सिंह, आशु सिंह, मोगर गांव की नंदू कंवर, हर्निया मंगरी निवासी प्रताप सिंह सहित अन्य ठामोणी ने बताया कि आए दिन गांवों में बिजली पोल से डीपी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इससे ठामोणी में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ठामोणी का कहना है कि क्षेत्र में पूर्ण से हुई कई चोरियों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे चोरों के हासले और बढ़ते जा रहे हैं।

ट्रक बाइक भिड़ंत में युवक की मौत

गंगापुर सिटी । सर्वाइमाधोपुर गंगापुर मेगा हाइवे के मीनापाडा गांव के पास एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की शिनाखा करौली के सैमरदा गांव निवासी युवक गौरव मीणा (22) के रूप में हुई है। यह घटना शुक्रवार शाम करीब 4.30 से 5 बजे के बीच मीनापाडा और जीवद नदी के बीच हुई। जानकारी के अनुसार मृतक गौरव मीणा पुत्र विनोद मीणा बाटोडा से अपनी मौसी के गांव कडी सोपडी जा रहा था। इसी दौरान सर्वाइ माधोपुर रोड पर एक ट्रक और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार गौरव मीणा गंभीर रूप से

घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस और ग्रामोणी की मदद से घायल युवक को तत्काल गंगापुर सिटी के सरकारी जिला अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने गौरव मीणा को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया। शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

धूल-धुआं प्रदूषण से हर घर में बीमारियां

पाटन । निकटवर्ती ग्राम पंचायत स्यालोदंडा में अवैध रूप से संचालित हो रहे क्रेशर प्लांटों से निकलने वाली जहरीली धूल और धुएँ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, इलाके में फैले प्रदूषण के कारण सैकड़ों लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामोणी का कहना है कि क्रेशर संचालकों ने नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर लगभग 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में धूल का गुबार फैला दिया है जिस कारण क्षेत्र का प्रदूषण स्तर 300 से 400 रहता है, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। स्थिति यह है कि अधिकांश घरों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएँ साँस, त्वचा और आँखों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रदूषण इतना अधिक है कि दिन में भी कई बार दृश्यता कम हो जाती है और हवा में भारी धूलक लगातार तैरते रहते हैं। ग्रामोणी ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की माँग की है, ताकि अवैध क्रेशर प्लांटों को बंद कर क्षेत्र में फैल रही गंभीर बीमारी की रोकथाम की जा

सके। इस बारे में ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को प्रस्ताव की कोपी भिजवा कर कार्यवाही की माँग कर चुके हैं। वहीं ग्रामोणी ने बताया है कि इलाके में स्थित चिड़ीमार पहाड़ पर खनन माफिया इतना दुस्साहस कर रहे हैं कि वह वन विभाग की पहाड़ियों में से दिन रात धड़ल्ले से अवैध खनन करके पत्थर चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से क्रेशरों पर डाल रहे हैं। जबकि इलाके में पहले भी ग्रामोणी की शिकायत पर वन विभाग के द्वारा कई बार कार्यवाही की जा चुकी है लेकिन खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तथा चिड़ीमार पहाड़ में जो कि क्वार्टरजाइट पत्थर का पहाड़ है उसमें अवैध खनन कर अपने क्रेशर प्लांट को चला रहे हैं जो ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा खनन करके क्रेशर प्लांटों पर पत्थर डाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्यालोदंडा में वन विभाग की 205 हेक्टेयर जमीन है जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा राजस्थान में तो दूसरा हिस्सा हरियाणा में पड़ता है।

युवा महोत्सव 15 को

झुंझुनूं, । मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा सत्र 2025-26 राजस्थान युवा बोर्ड युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की लुप्त एवं दुर्लभ लोक कला एवं संस्कृति को संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन के लिए राजस्थान प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनूं खेल मैदान में 15 दिसंबर को सुबह नौ बजे से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक राजेश मील ने बताया कि इस युवा महोत्सव में राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकृत 15 से 29 आयु वर्ग के युवा भाग लेंगे। युवाओं के लिए लोक नृत्य सामूहिक, लोक गायन सामूहिक, एकल नृत्य राजस्थानी, एकल गायन राजस्थानी, भाषण, कविता लेखन, चित्रकला, कहानी लेखन, प्रदर्शनी, विज्ञान मेला, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

अजय पुरोहित ने चौथी बार जीते

बीकानेर,(कासं)। बार एसोसिएशन का चुनाव अजय पुरोहित ने जीता। पुरोहित ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी तेजकरण सिंह को 150 वोट से हराया। पुरोहित को 999 वोट मिले, वहीं तेजकरण को 849 वोट मिले। शेष दो उम्मीदवार सौ वोट भी हासिल नहीं कर सके।

मुख्य चुनाव अधिकारी अविनाश चंद्र ने बताया कि कुल वोट में अजय पुरोहित को 999, तेजकरण सिंह को 849, सुखराम मेघवाल को 82 और सकीना बानो को 69 वोट मिले। कुल 2296 वोट थे। महिलाओं के चार सौ वोट हैं। अजय पुरोहित ने चौथी बार अपनी जीत दर्ज की है। इससे पहले वो तीन चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनके साथ अधिकांश धड़े शामिल थे।

रामकृष्ण दास गुप्ता और उनके साथी एडवोकेट पुरोहित के साथ खड़े नजर आए। वहीं कमल नारायण पुरोहित का गुप भी अजय पुरोहित के समर्थन में था। वहीं युवाओं का बड़ा गुप तेजकरण सिंह के साथ था। इस बार दोनों प्रमुख उम्मीदवारों ने अलग-अलग चुनाव कार्यालय खोल रखे थे।

वरिष्ठ एडवोकेट अजय पुरोहित और युवा उम्मीदवार तेजकरण सिंह राठौड़ के साथ ही सुखराम मेघवाल और सकीना ने मुकाबले को रोचक बनाने का प्रयास किया लेकिन दोनों उम्मीदवार सौ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। पुरोहित ने जीत के बाद कहा कि हम बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बीकानेर में बहुत ज्यादा केस हैं।

लापरवाही से चूक, प्लास्टर करते वक्त पैर के अंदर ही छोड़ी सर्जिकल ब्लेड

बीकानेर, (कासं)। सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते एक बच्चे के पैर पर प्लास्टर करते वक्त नर्सिंग कर्मचारी ने सर्जिकल ब्लेड छोड़ दी। पांच दिन तक बच्चा तेज दर्द की शिकायत करता रहा। परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि सर्जिकल ब्लेड से बच्चे के पैर में जगह-जगह घाव हो चुके हैं। इलाज में घोर लापरवाही का ये मामला बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर का है। बच्चे का पैर 9 दिसम्बर को फ्रैक्चर हुआ था। इसी दिन परिजन ने ट्रोमा सेंटर पर प्लास्टर करवाया था। बीकानेर शहर में छोपों का मोहल्ला में मक्का मस्जिद इलाके में रहने वाले पीड़ित बच्चे उवेश राजा के दादा मोहम्मद अयूब लोधा ने बताया कि 9 दिसम्बर को मेरे पेटे को पैर में चोट लगी थी। हम उसे पीबीएम हॉस्पिटल ले गए। वहां ट्रोमा सेंटर पर बच्चे को दिखाया तो डॉक्टर ने एक्सरे कराने को कहा।

एक्सरे में घुटने से टखने के बीच

सिगड़ी से लगी आग, झुलसी महिला ने दम तोड़ा

श्रीगंगानगर, (कासं)। सिगड़ी तापते समय एक 80 साल की महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली। झुलस जाने से हालत खराब हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां तीन दिन इलाज के बाद मौत हो गई। हादसा रात को देवनगर नर्सरी के निकट निवासी परिवार में हुआ।

परिवारी मृतका के पोते राहुल दास ने पुरानी आबादी पुलिस को दिए परिवाद में बताया कि उसकी दादी रामदुलारी रात को सर्दी से बचाव के लिए सिगड़ी जलाकर रखती थी। घटना की रात सिगड़ी की आग उनके पहने हुए कपड़ों ने पकड़ ली। इससे वे कुछ 70 फीसदी झुलस गईं। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सिगड़ी से तेज या चार फीट दूर रहे, कमरे का गेट खुला रहे मनीराम स्वामी, रिटा. चीफ फायरमैन लकड़ी

संजू काजला ने पंचे भेंट किए

नोखा, (कासं)। शहीद कॉन्स्टेबल बजरंग लाल राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल काकड़ा में पूर्व प्रधानाध्यापिका संजू काजला ने अपने पिता की पांचवी पुण्यतिथि पर चार पंचे भेंट किए।

उन्होंने यह सहयोग अपने पिता की स्मृति में सेवाभाव से किया। इस अवसर पर परिसर में एक सादरपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल की अध्यापिका निर्मला गहलोल ने बताया कि संजू काजला पहले भी अपने पिता की पुण्यतिथि पर विद्यालय विकास के लिए लगातार सहयोग करती रही हैं। इससे पूर्व उन्होंने विद्यालय को एक इलेक्ट्रिक वेल, 14 कुर्सियां और 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी।

इस सहयोग से विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिली है। इस काव्यार्थ, राजेन्द्र बिर्जपुरी, नीरज, पूजा बिवाड़ी, राजेन्द्र बिर्जपुरी, मनोभायादाव, अनिता चौधरी, तुलसी और शांति सहित शिक्षकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने काजला के योगदान की प्रशंसा की।

सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे विकास रथ

बीकानेर, (कासं)। राज्य सरकार के कार्यक्रम के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत शनिवार को हुई। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर ने बीकानेर के सातों विधानसभा क्षेत्रों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जन कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को आमजन तक पहुंचाएंगे रथ

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह रथ, राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचायेगा। यह रथ दूरस्थ गांव और ढाणियों तक जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत दो वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। यह रथ आमजन तक इनकी जानकारी पहुंचायेगा। उन्होंने विकास रथों के संचालन की सघन मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित रूट के



राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए विकास रथों को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अनुसार इनका संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर सहित अन्य उच्च अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग करें। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने परिवहन विभाग द्वारा निकाली गई सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाई। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत आठों रिक्शा तथा दुपहिया वाहन चालकों ने रैली के माध्यम से सड़क

सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। उन्होंने 25 दिवसीय दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट विनित्त किए। जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने बीकानेर से सुशासन पखवाड़ा रथ यात्रा की सफल शुरुआत पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह रथ यात्रा सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ

जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाए। इस दौरान विधायक सिद्धिकुमार, जेटानंद व्यास, श्याम पंचाश्या, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

छह हजार से अधिक यूरिया बैग की आपूर्ति

लूणकरनसर, (कासं)। खाद की किल्लत के बीच कृषि विभाग ने सहकारी समितियों और निजी दुकानदारों को छह हजार से अधिक यूरिया बैग की आपूर्ति की। प्रशासन और कृषि विभाग रविवार को किसानों को टोकन बांटकर यूरिया खाद का वितरण करवायेगा।

यूरिया के ट्रेक पहुंचने शुरू हो गए थे। शनिवार शाम तक सभी सहकारी समितियों और दुकानदारों तक यूरिया पहुंच गया। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी विनोद सिंह ने बताया कि बीकानेर में इफको यूरिया के रैक से लूणकरनसर क्षेत्र की विभिन्न समितियों और एजेंसियों को यूरिया आवंटित किया गया है। इनमें तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति लूणकरनसर, ग्राम सेवा सहकारी समिति सुई, ग्राम सेवा सहकारी समिति अरजनसर, किसान एग्री सहकारी समिति कालू, महिदा एग्री एजेंसी कालवास और अनन्दाटा एग्री एजेंसी नकोदेसर शामिल हैं।

यूरिया के ट्रेक पहुंचने शुरू हो गए थे। शनिवार शाम तक सभी सहकारी समितियों और दुकानदारों तक यूरिया पहुंच गया। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी विनोद सिंह ने बताया कि बीकानेर में इफको यूरिया के रैक से लूणकरनसर क्षेत्र की विभिन्न समितियों और एजेंसियों को यूरिया आवंटित किया गया है। इनमें तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति लूणकरनसर, ग्राम सेवा सहकारी समिति सुई, ग्राम सेवा सहकारी समिति अरजनसर, किसान एग्री सहकारी समिति कालू, महिदा एग्री एजेंसी कालवास और अनन्दाटा एग्री एजेंसी नकोदेसर शामिल हैं।

यूरिया के लिए सुबह पांच बजे से लाइन में लगे किसान

पूगल, (कासं)। पूगल क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी कमी से किसान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गेहूं, चना, सरसों, जौ और इसबगोल जैसी रबी की फसलों के लिए यूरिया खाद आवश्यक है। इसकी अनुपलब्धता के कारण किसान अपनी फसल के उत्पादन को लेकर चिंतित हैं।

पूगल स्थित प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद की एक खेप आने की सूचना मिलते ही किसान सक्रिय हो गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर किसान अल सुबह 5 बजे से ही लाइनों में खड़े हो गए। 200 दिनों से पहले ही लगभग 150 से 200 किसानों की लम्बी कतार लग चुकी थी। अपनी फसलों को बचाने की मजबूरी में किसान इतनी ठंड में भी कतारबद्ध खड़े दिखाई दिए।

किसानों का कहना है कि यह स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है। यूरिया खाद की किल्लत के साथ-साथ समिति के व्यवस्थापक से संपर्क करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं

युवती से मोबाइल छीन ले गए

बीकानेर, (कासं)। महिला पुलिस थाने के पास एक बाइक सवार ने झपट्टा मारकर युवती के हाथ से मोबाइल छीना और फरार हो गया। राहगीरों ने पीछा कर उसका वीडियो बनाया लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका।

रानीबाजार इंडस्ट्रियल एरिया की 5 नंबर गली में कुष्णा एकेडमी में टीचर प्रियंका अलवर्ट व्यास कॉलोनी में रहती हैं। स्कूल से छुट्टी होने के बाद टैक्सी में सवार होकर पवनपुरी की ओर जाने वाले रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचीं और वहां से पैदल रवाना हुईं। मरुघा कॉलोनी में महिला पुलिस थाने से मोबाइल हाथ में लिया जा रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार पीछे अचानक पीछे से आया और झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार फरार हो गया। युवती ने शोर मचाया तो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बाइक सवार का पीछा किया और उसका भागते हुए वीडियो बना लिया।

बाइक सवार फरार हो गया। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। युवती व्यास कॉलोनी पुलिस थाने पहुंचीं। जेएनबीसी में रिपोर्ट दी गई है। अगर आप मोबाइल हाथ में लेकर या बात करते सड़क पर चल रहे हैं तो सतर्कता बरतें। क्योंकि बाइक सवार बदमाश ऐसे ही लोगों की फिराक में रहते हैं और झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। व्यास कॉलोनी, पवनपुरी, म्यूजियम के पास सहित अनेक क्षेत्रों में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं।

पूगल क्षेत्र में कुल 4 लाख 510 हेक्टेयर में रबी की फसलों की बुवाई हुई

पूगल क्षेत्र में कुल 4 लाख 510 हेक्टेयर में रबी की फसलों की बुवाई हुई। यूरिया की कम आपूर्ति से वितरण व्यवस्था लड़खड़ाई।

मिलता। दूर-दराज के चक ढाणियों में बसे किसानों को अक्सर यूरिया वितरण हो जाने के बाद सूचना मिलती है। कई किसानों ने आरोप लगाया कि व्यवस्थापक खाद की गाड़ी पहुंचते ही अपने निजी लोगों को पहले सूचित करते हैं, जिससे अन्य किसान हर बार यूरिया से वंचित रह जाते हैं। इस साल जिले में कुल 4 लाख 510 हेक्टेयर में रबी की फसलों की बुवाई हुई है। इन फसलों के लिए लगभग 80,500 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है लेकिन अभी तक आधे से भी कम आपूर्ति होने के कारण वितरण व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है।

छतरगढ़ में वन भूमि से कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू

लूणकरनसर, (कासं)। बीकानेर जिले के लूणकरनसर क्षेत्र में एक व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई। यह घटना मकड़ारस की रोही में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लूणकरनसर थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि मकड़ारस निवासी गोविन्दराम कुम्हार ने पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार उनके चाचा परताराम कुम्हार सुबह करीब 8 बजे रोही में गायें चराने गए थे। शाम 7-8 बजे तक परताराम घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खेतों में उन्हें परताराम बेहोशी की हालत में मिले। आशंका है कि उन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। परिजनों ने तुरंत परताराम को लूणकरनसर के उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बीकानेर, (कासं)। जिले में वन विभाग की जमीन पर लम्बे समय से हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। छतरगढ़ क्षेत्र में सैकड़ों बीघा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध काशत को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

जिला वन अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व के सहयक वन संरक्षक सूर्यप्रताप सिंह और दंतौर रेंजर भैरवेंद्र सिंह की टीम ने 66 आरडी क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान 11 बीएलडी, 3 एसडब्ल्यूएम और 4 एसडब्ल्यूएम क्षेत्रों में वन भूमि पर की जा रही अवैध काशत और मौके पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। इसके बाद कब्जे हटाने की

कार्रवाई शुरू की गई। जिला वन अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि छतरगढ़ वन मंडल के अधीन रेंज दंतौर में अवैध अतिक्रमण और काशत के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत वन भूमि पर स्थित सभी प्रकार के अतिक्रमण और अवैध काशत को चिन्हित कर संबंधित लोगों को बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में छतरगढ़ वन मंडल की सभी रेंजों में इसी तरह का अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा। वन विभाग की अचानक और ताबडतोड़ कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कम्प मच गया। विभाग की टीम मौके पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे कई स्थानों पर अवैध रूप से की जा रही काशत को रोका गया है। इस दौरान रेंज स्टाफ वनरक्षक रामसिंह, रामदयाल, धर्माराम, श्रवण चौधरी, सुनील कुमार, राकेश कुमार, रामलाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। छतरगढ़ सहित जिले के कई क्षेत्रों में वन विभाग की जमीन पर लम्बे समय से अवैध काशत की जा रही थी। खेतों से सटी वन भूमि पर फसल बोकर उत्पादन लिया जाता था।

राजस्थानी को मान्यता एवं दूसरी राजभाषा का हक मिले: रंगा



इटालियन राजस्थानी साहित्यकार एल. पी. टैस्सीटोरी की जयंती पर उनकी मजार पर राजस्थानी साहित्यकारों ने श्रद्धांजलि दी।

वर्षों पुराना साहित्यिक-सांस्कृतिक वैभवपूर्ण इतिहास है। साथ ही हमारी मातृभाषा राजस्थानी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सभी मानदण्डों पर खरी उतरती है। ऐसे में हमारी मातृभाषा को शीघ्र मान्यता केन्द्र व राज्य सरकार को देनी चाहिए।

चाहिए। रंगा ने कहा कि राजस्थानी को मान्यता मिलना ही डॉ टैस्सीटोरी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉ. फारूख चौहान ने कहा कि राजस्थानी भाषा भारतीय भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसी भाषा की अनदेखी करना दुःखद पहलू है। जाकिर अदीब ने कहा कि अब सरकारों को भाषा के प्रति अपना सकारात्मक व्यवहार रखते हुए भाषा की मान्यता पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। मधुरिमा सिंह ने कहा कि टैस्सीटोरी के महत्त्वपूर्ण कार्यों को जन-जन तक ले जाने का कार्य कमल रंगा ने किया है वह महत्वपूर्ण है। गोपाल कुमार कुंठित ने कहा कि हमें राजस्थानी मातृभाषा को अधिक से अधिक जीवन व्यवहार में प्रयोग लेनी चाहिए। महेन्द्र जोशी ने कहा कि राजस्थानी भाषा के प्रति हमें मान्यता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए।

कार ने बाइक सवार को कुचला

श्रीगंगानगर, (कासं)। मीरा चौक से गंगनहर पुल एसएसबी रोड की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा तय है। लेकिन इस पर 100 किमी/घंटा से भी तेज रफ्तार में इलेक्ट्रिक एसयूवी बीवाड़ी 7 ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक तीन ई छोटी गली नंबर 8 निवासी 30 वर्षीय नवीन यादव की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसकी मासूम 7 साल की बेटी टियाशा गंभीर रूप से घायल हो गई। टियाशा की निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा एसएसबी रोड पर पानी वाली टंकी के निकट हुआ। जिस कार से हादसा हुआ वह करीब 50 लाख रूपए कीमत की बताई जा रही है। इस बीच तीन ई छोटी के लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जवाहर नगर थाने पहुंचे और धरना लगा दिया। कार चालक वृंदावन विहार नारासी लोकाश गोयल को पुलिस ने जवाहर नगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

सार-समाचार

श्मशान भूमि में कार्यों का शिलान्यास



विधायक जेटानंद व्यास ने श्मशान भूमि भाटोलाई तलाई में होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया।

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेटानंद व्यास ने शनिवार को गवरा देवी श्मशान भूमि भाटोलाई तलाई में टीनशेड, चौकी बनाने तथा चारदीवारी ऊंची करने के कार्य का शिलान्यास किया। विधायक निधि योजना वर्ष 2025-26 के तहत इस कार्य पर 10 लाख रूपए व्यय होगा। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्य करवाए गए हैं। विधायक निधि और राहत आमजन को मिल रही है। उन्होंने कहा कि व्यय आमजन पर पूर्ण करवाया गया। विधि में भी विधायक निधि का व्यय समयान की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि युवा कल्याण के राज्य सरकार के श्रेष्ठ के मध्यनगर बीकानेर (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र में रोजगार सहायता शिपिर का आयोजन 17 दिसम्बर को किया जा रहा है। क्षेत्र के युवा इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। इस दौरान जे.पी. व्यास, किशन चौधरी, जोगेन्द्र शर्मा, विजय पनिया, वरुणलाल हर्ष, प्रतीक स्वामी, दिनेश चांडक और विमल चौहान आदि मौजूद थे।

ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी शुरू



हिन्दी सिनेमा के 100 साल ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि इक्बाल हुसैन समेजा ने शुभारंभ किया।

बीकानेर, (कासं)। अमन कला केन्द्र द्वारा राजमाता सुदर्शना कला दीर्घा होटल लाल जी के सामने स्टेशन रोड पर दो दिवसीय ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी व फिल्म संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को सुदर्शन कला दीर्घा गंगरी भंडार में किया गया। संस्था के अध्यक्ष एम. रफीक कादरी ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि इक्बाल हुसैन समेजा डायरेक्टर रॉयल इन रानी बाजार थे। अध्यक्षता संयुक्त रूप से एन. डी. रंगा अध्यक्ष सख्ता संगम व डॉ मीना आसोपा ने की। विशिष्ट अतिथि डॉ सीताराम गोठवाल, डॉ विजयलक्ष्मी व्यास, मास्टर अमीर महबूब रंगेज, अर्पिता गुप्ता, अरुण पांडे थे। इस अवसर पर गावक कलाकार एम. रफीक कादरी ने गीत प्रस्तुत किए। कादरी ने बताया कि 14 दिसम्बर को फिल्म अभिनेता राजेन्द्रपूर की 101 वीं जयंती जन्मदिन अभिनय स्मार्ट दिलीप कुमार की जयंती पर दोपहर 11 बजे से पुनः फिल्म गीतों का गंगारं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविन्द मिश्रा, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी होंगे। अध्यक्षता संयुक्त रूप से नरेश चुग व डॉ सी.एस. मोदी करेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉ श्याम अग्रवाल, डॉ गौरव गोम्बर, डॉ नवनीत सुधार, डॉ आनंद विनोद, प्रकाश पुरालिया, मा. सदीक चौहान, संतोष तिवारी, संजीव ऐन होंगे। प्रसिमा के 100 साल ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी 1930 से 1950 के फ्लेक्स बैनर व 1951 से ओरिजिनल फिल्मों के पोस्टर प्रदर्शनी व संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

बजरी खान धंसने से मंदिर खतरे में

नोखा, (कासं)। उगमपुरा क्षेत्र में बजरी की एक खान धंसने से हनुमान मंदिर और सरकारी जनता क्लीनिक का भवन खतरे में आ गया है। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। खान धंसने के कारण मंदिर की चारदीवारी जमीन में समा गई। मंदिर और क्लीनिक के पास रहने वाले सैकड़ों परिवारों को चिंता होने लगी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस जगह पर पहले भी बजरी खान धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे दो बार गहरे गड्ढे बन गए थे। इसके बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। जमीन धंसने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने प्रशासन से तत्काल बजरी खनन पर रोक लगाने की मांग की। लोगों ने मंदिर और जनता क्लीनिक के भवनों को सुरक्षित करने की भी अपील की।

राजस्थान सड़क, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)			
क्रमांक: निम्न/2025/4939	सर्वजनिक आपूर्ति सूचना	दिनांक: 04.12.2025	
सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि श्री विकास कुमार गोखर पुत्र श्री राजनन्दन विद्यार्थी निवासी 45 वीं बली, गली नं. 12, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित अनावृत मूखण्ड का न्यास रिहाई में नमानरण हुए अवेदन किया गया है। उक्त मूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिहाई एवं अवेदन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की रिपिटी निम्नानुसार है -			
न्यास रिहाई के अनुसार मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण
भूमि का विवरण	मूल मूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण	
खण्ड 6 ई छोटी मूखण्ड नं. 43	उक्त मूखण्ड का विवरण सड़क संख्या 65 फीट मूखण्ड संख्या 8-9	श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम	श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम
दिनांक 20.10.2025	दिनांक 27.02.2025	दिनांक 07.04.2025	दिनांक 07.04.2025
मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615
मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615

राजस्थान सड़क, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)			
क्रमांक: निम्न/2025/4940	सर्वजनिक आपूर्ति सूचना	दिनांक: 04.12.2025	
सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम निवासी 45 वीं बली, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित अनावृत मूखण्ड का न्यास रिहाई में नमानरण हुए अवेदन किया गया है। उक्त मूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिहाई एवं अवेदन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की रिपिटी निम्नानुसार है -			
न्यास रिहाई के अनुसार मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण
भूमि का विवरण	मूल मूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण	
खण्ड 6 ई छोटी मूखण्ड नं. 43	उक्त मूखण्ड का विवरण सड़क संख्या 65 फीट मूखण्ड संख्या 8-9	श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम	श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम
दिनांक 20.10.2025	दिनांक 27.02.2025	दिनांक 07.04.2025	दिनांक 07.04.2025
मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615
मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)			
क्रमांक: निम्न/2025/4962	सर्वजनिक आपूर्ति सूचना	दिनांक: 04.12.2025	
सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि श्री विकास कुमार गोखर पुत्र श्री राजनन्दन विद्यार्थी निवासी 45 वीं बली, गली नं. 12, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित अनावृत मूखण्ड का न्यास रिहाई में नमानरण हुए अवेदन किया गया है। उक्त मूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिहाई एवं अवेदन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की रिपिटी निम्नानुसार है -			
न्यास रिहाई के अनुसार मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण	अवेदन के द्वारा मूखण्ड का विवरण
भूमि का विवरण	मूल मूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण	
खण्ड 6 ई छोटी मूखण्ड नं. 43	उक्त मूखण्ड का विवरण सड़क संख्या 65 फीट मूखण्ड संख्या 8-9	श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम	श्री अतिरिक्त अवेदन द्वारा पंजीकृत वेदनाम
दिनांक 20.10.2025	दिनांक 27.02.2025	दिनांक 07.04.2025	दिनांक 07.04.2025
मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615
मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615	मौज में मूखण्ड संख्या 615

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)			
क्रमांक: निम्न/2025/4962	सर्वजनिक आपूर्ति सूचना	दिनांक: 04.12.202	

‘पेपर लीक में कांग्रेस सरकार नंबर वन थी, हमने सत्ता में आते ही कड़ी रोक लगाई : दिया कुमारी

दिया कुमारी ने पेश किया सरकार का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड

अजमेर। राजस्थान सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर दौरे पर रहीं। यहाँ जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने

■ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न जगहों के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार हर साल अपना रिपोर्ट



राजस्थान सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर दौरे पर रहीं।

में प्रदेश में 90 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्तियों दी गई हैं, जबकि डेढ़ लाख भर्तियाँ अभी प्रक्रियाधीन हैं,

जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्राइम रेट में 19

फीसदी तक की गिरावट आई है, जिससे प्रदेश सुरक्षित हुआ है। वहीं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से अब पर्यटकों की

आवक बढ़ी है और प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला भी तेज हुआ है। दिया कुमारी ने पेपर लीक मामले पर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘पेपर लीक में कांग्रेस सरकार नंबर वन थी, लेकिन हमने सत्ता में आते ही इस पर कड़ी रोक लगाई है। हमारी सरकार के दो साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।’ उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल वादे करती थी, जबकि हम काम करके दिखाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाथी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारीगिर चौधरी विधायक अनिता भदेल ने भी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

मंच पर देवनाथराय बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भट्टाना सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए सुसज्जित विकास रथों को रवाना किया गया, जो गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे।

‘तेस्सितोरी ने राजस्थानी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई’

जोधपुर। आजादी से पूर्व राजपूताना में प्राचीन डिंगल-पिंगल, चारण-चारणेत, जैन-जैनतर, लोक-संत साहित्य एवं ऐतिहासिक-पुरातात्विक स्रोत की खोज कर डॉ.तेस्सितोरी ने राजस्थानी भाषा साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। यह विचार प्रतिष्ठित विद्वान डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर ने जेएनवीयू के राजस्थानी शोध परिषद एवं राजस्थानी विभाग द्वारा नया परिसर स्थित राजस्थानी सभागार में आयोजित डॉ. एल. पी. तेस्सितोरी के 138 वें जन्म जयंती समारोह पर आयोजित राजस्थानी व्याख्यान में व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने तेस्सितोरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को विस्तार से उजागर करते हुए कहा कि उनकी आलोचनात्मक दृष्टि अद्भुत थी। राजस्थानी शोध परिषद के सचिव विश्वेश्वर ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि कला शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर (डॉ.) औतारलाल मीणा थे। उन्होंने कहा कि मातृभाषा हमारी पहचान है इसलिए अपने दैनिक जीवन में इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित ने डॉ. एल. पी. तेस्सितोरी को धुन का धनी बताते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थानी भाषा-साहित्य के की खोज कर जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो वाकई में उल्लेखनीय है।

गंगनहर में खखां हेड पर पानी की आवक घटकर हुई 1718 क्यूसेक

श्रीगंगानगर। पंजाब से बीकानेर कैनाल में पानी के उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। राजस्थान बॉर्डर के खखां हेड पर गंगनहर में पानी की आवक घटकर 1718 क्यूसेक रह गई। इस माह बीकानेर कैनाल में प्रदेश के पानी का हिस्सा 1800 क्यूसेक है तथा तय हिस्से का पानी नहीं मिलने के कारण किसानों में आक्रोश है। पंजाब में बीकानेर कैनाल में आरडी 45 से शुरूवार शाम को 2040 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जा रहा था तथा राजस्थान बॉर्डर के खखां हेड पर सिर्फ 1718 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। पानी की आवक कम होने के कारण वरीयताक्रम के अनुसार गंगनहर से जुड़ी पीएस नेतेवाला व हिरणावाली वितरिकाओं में पानी का प्रवाह शुरू नहीं हो पाया। पीएस वितरिका क्षेत्र के किसानों को पिछली बार भी रेगुलेशन के अनुसार तय समय पर पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की सिंचाई बारियां पीटी थी। इस बार पीएस वितरिका सुबह 6 बजे खुलनी थी लेकिन नहीं खुली, इस कारण इस वितरिका क्षेत्र के किसानों की सिंचाई बारियां पीट गई। नेतेवाला व हिरणावाली वितरिकाओं में पानी का प्रवाह शुरू होना था, लेकिन गंगनहर में पंजाब से पानी की आवक कम होने के कारण शुरू नहीं हो पाया। इस कारण इन वितरिका क्षेत्र के किसानों को भी

■ पीएस नेतेवाला और हिरणावाली वितरिकाओं में शुरू नहीं हो पाई पानी की आपूर्ति

सिंचाई सुविधा नहीं मिल पाई। हरबिंद सिंह गिल, प्रोजेक्ट चेयरमैन गंगनहर पंजाब के अधिकारी ने बताया कि पर्याप्त पानी होने के बावजूद बीकानेर कैनाल को तय हिस्से का भी पानी नहीं दे रहे हैं। इस दिनों हमारे यहाँ सरसों, जौ, चना व गेहूँ की फसलों में सिंचाई पानी की मांग बनी हुई है। लेकिन पंजाब सिंचाई विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तथा बीकानेर कैनाल में प्रदेश के तय हिस्से का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में प्रशासनिक व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है तथा समस्या के समाधान करने की मांग की है। श्रीगंगानगर करणीची, एमएलए, एमएलए व रिडमलसर वितरिकाओं का सिस्टम विगड़ा: वरीयताक्रम के अनुसार करणीची, एमएलए, एमएलए व रिडमलसर आदि वितरिकाओं में शुरूवार को पानी का प्रवाह शुरू होना है, लेकिन पंजाब से बीकानेर कैनाल में पानी की आवक कम होने के कारण गंगनहर का रेगुलेशन सिस्टम विगड़ा हुआ है।

अजमेर में प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे हुई बड़ी लूट का खुलासा

अजमेर, 13 दिसंबर। क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे हुई 23 लाख 39 हजार रुपये की लूट की सनसनीखेज वारदात का अजमेर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में अंतरराज्यीय लूट गिरोह के सरगना सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी को गुजरात के मोरबी औद्योगिक क्षेत्र से दबोचा गया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अजमेर जिले के विभिन्न इलाकों से की गई है।

थानाधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की गई। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके फरारी मार्ग का विश्लेषण किया गया। तकनीकी सख्तियों और मुखबिर तंत्र की मदद से पता चला कि गैंग का सरगना तिहारी निवासी सुरेंद्र चौधरी अपने साथियों के साथ गुजरात के मोरबी सिटी के

■ अंतरराज्यीय गैंग का सरगना गुजरात से दबोचा गया, नशे और ऐंश के लिए रची थी साजिश

इंडस्ट्रियल एरिया में छिपा हुआ है। पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर गुजरात रवाना किया, जिसने लगातार गिरगारी और सघन तलाश के बाद सरगना सहित आरोपियों को गिरफ्तार

कर लिया। अन्य आरोपियों को गांव तिहारी, थाना श्रीनगर तथा अजमेर शहर से दबोचा गया। पुछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि महेंगे शौक और नशे की लत पूरी करने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस लूट को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार प्रार्थी कमल पुत्र तोर्थदास, निवासी कुट्टी की टाल के पीठ, चौमसियावास रोड अजमेर, स्कूटी से प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे वाले गेट

के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी स्कूटी को टेकर मारकर नकदी से भरी थैली छीन ली और दो वाहनों में सवार होकर फरार हो गए थे। इस संबंध में पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज में प्रकरण संख्या 357/2025 धारा 309(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से गश्त पुछताछ जारी है तथा लूटी गई राशि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

थली गांव में बदमाशों ने की फायरिंग

गंगापुर सिटी। गंगापुर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में तीन थानों एवं आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस चौकियां होने के बाद भी दहशतवादी में पुलिस का भय नहीं है जिससे आमजन को डर के साय में जीना पड़ रहा है। शनिवार को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच गंगापुर सिटी से एक बार फिर बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थली गांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार थली गांव निवासी कमलेश गुर्जर को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गोली युवक के

सोने में लंगकर आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को गंगापुर सिटी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रैफर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा

हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी और जांच तेज कर दी गई है। इस मामले में सदर थाना गंगापुर सिटी के एसआई बच्चू सिंह ने बताया कि थली गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस गोली कांड के कारणों, आपसी रंजिश अथवा अन्य एंगल से जांच कर रही है। घटना के बाद थली गांव सहित आसपास के इलाकों में भय का माहौल बना हुआ है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश चल रहा है।

‘कुछ लोगों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दी’

जोधपुर, (कास)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी मानसिकता हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देती रही है। शनिवार को जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि ऐसे लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बंदे मातरम् जैसे पवित्र गीत के भी टुकड़े किए और आज भी वही मानसिकता बनी हुई है। शेखावत ने कहा कि आज भी कुछ लोग राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के मंत्र को अपने राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू में तौलते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में नया गवर्नंस ऑर्डर लागू हुआ, जिसके चलते देश के गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। लोगों इससे काफी राहत मिली। कई लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की।

सतीश पूनियां के स्वागत में सुबह से किसानों और कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा

श्रीगंगानगर/ जयपुर,। राजस्थान और हरियाणा के निरंतर प्रवास पर भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा



राजस्थान और हरियाणा के निरंतर प्रवास पर भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां श्रीगंगानगर जिले के प्रवास पर रहे।

एक दूसरे के प्रति लगाव और समर्पण है कि पूरे राजस्थान में और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पहचानते हैं। सतीश पूनियां ने सुबह श्रीगंगानगर, सर्किट हाउस में जिले भर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और

कार्यकर्ताओं के साथ इतने घुले-मिले हैं कि पूरे राजस्थान में और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पहचानते हैं। सतीश पूनियां ने सुबह श्रीगंगानगर, सर्किट हाउस में जिले भर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और

जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और वहां की स्थानीय समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उचित समाधान के लिए दिशा निर्देश दिये। इसके अलावा सतीश पूनिया ने पदमपुर, अमरपुरा जाटान, सूरतगढ़, रघुनाथपुरा, जैतसर में भी किसानों एवं कार्यकर्ताओं

गड़बड़ी मिली तो हट सकती है एथेनाॅल फैक्ट्री

■ किसानों की मांगों को लेकर होगा रिव्यू
■ किसान आंदोलन में बनी सहमति

हनुमानगढ़। टिब्बी (राड़ीखेड़ा) में आंदोलन बीती रात स्थगित हो गया। प्रशासन और किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बनी। फैक्ट्री में गड़बड़ी मिलने पर हटाने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर रिव्यू होगा। इससे पहले ड्यूनि एथेनाॅल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री का विरोध दोपहर तक जारी था। उपद्रव मामले में 107 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 40 लोग हिरासत में लिए जा चुके थे। गोरतलब है कि 10 दिसंबर (बुधवार) को किसानों ने जिले के

नाराजगी: 19 नवंबर 2025 पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण फिर शुरू हुआ। किसान नेता महंगा सिंह समेत 12 से अधिक किसान नेता गिरफ्तार। 20-21 नवंबर 67 लोगों ने गिरफ्तारी दी। 10 दिसंबर की दोपहर किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर राड़ीखेड़ा गांव स्थित फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। दोपहर तोड़ दी थी। इस बीच पुलिस-किसानों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बवाल में कांग्रेस विधायक सहित 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कुछ घायल टिब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके हैं। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर भाग गए हैं।

फैक्ट्री की दीवार तोड़ने से पहले किसानों ने महापंचायत भी की थी। नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें लिखित में फैक्ट्री का काम रोकने का आश्वासन नहीं दिया था। चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड ड्यूनि एथेनाॅल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राड़ीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनाॅल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है प्लांट केंद्र के एथेनाॅल ड्रैडेट पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। सितंबर 2024 से जून 2025 तक लगभग 10 माह शांतिपूर्ण चिरोध चला। जुलाई 2025 में विरोध तेज हुआ। कंपनी ने कारदीवारी (बाउंड्री वॉल) का निर्माण शुरू किया, जिससे किसानों का गुस्सा भड़का।

हटाने का आश्वासन भी दिया। हनुमानगढ़ में एथेनाॅल फैक्ट्री विवाद को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासन और संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच बैजूक चल रही है। बैजूक में सादुलशहर विधायक गुरुवीर बराड़, एडीजीपी वीके सिंह, आईजी हेमंत शर्मा, कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव और एसपी हरिशंकर शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल में शामिल विजेन्द्र पूनिया, पूर्व विधायक धर्मेश मोची और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिशोई भी मौजूद हैं। संघर्ष समिति की ओर से शबनम गोदार, जगजीत जग्गी सहित अन्य सदस्य वार्ता में भाग ले रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने कहा- एडीजी लगातार बयान दे रहे हैं कि किसानों ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था संभालना हमारा जिम्मा है। मैं एडीजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था संभालना आपका जिम्मा है, लेकिन गोली मारना आपका अधिकार है क्या हमारे पास ऐसे कई बुलेट हैं, जो हमें मिले हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें एक एसआई कह रहा है कि इन्हें गोली मार दो। मैं एडीजी साहब से कहना चाहता हूँ कि वे फैक्ट्री के डायरेक्टर नहीं बनें।

कार्यालय नगर निगम अलवर (राज0)
क्रमांक-न.नि.अल./एचबीएम/2025-26/13521 दिनांक- 10.12.2025
E-Procurement Notice Inviting Bid/2025-26
A Bid For "The Work of Catching Stray Animals like Bull, Cow, Calf, Heifer, Donkey, Buffalo, Hens, etc. Roaming in the City" is invited for interested bidders up to 2:00 PM on 22-12-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal: https://sppp.rajasthan.gov.in & https://proc.rajasthan.gov.in/ of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 20.00 Lac.
UBN No. - DL82526SLS0262798
Raj.Samwadi/25/15766 Commissioner

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति "विशिष्ट श्रेणी" बाएं (राज.)
क्रमांक- 3858-70 दिनांक- 10/12/2025
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
कृषि उपज मंडी समिति "विशिष्ट श्रेणी" बाएं द्वारा किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुदानित दर पर भोजन थाली व्यवस्था हेतु रजिस्टर्ड, प्रतिष्ठित फर्मों/अधिकृत डीलरों/प्रोकेयर्स को निम्नलिखित प्रपत्र में ई-प्रोक्वोरमेंट के माध्यम से स्तरीकृत ऑन लाइन निविदा ई-प्रोक्वोरमेंट बोली दिनांक 22.12.2025 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in या www.eproc.rajasthan.gov.in पर विद्यमान पोर्टल agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर भी देखी जा सकता है। निविदा की अनुमानित कुल लागत 75.00 लाख रु. है।
NIB CODE - DAM2526A0619, UBN No. - DAM2526WS0801071
सूचना संख्या/डी/25/15766

राजस्थान सरकार का उपक्रम
RIICO
GRAND LITER REFINERY
RAJASTHAN
DEPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक क्षेत्रों में संस्थानिक/वाणिज्यिक/ग्रुप हाउसिंग एवं गैर औद्योगिक भूखण्डों का
सरल ई-नीलामी के माध्यम से

आवंटन

कुल भूखण्ड	391	अप्रत्याक्ष/कर्मि हो/दिलरेक्ट	13	वाणिज्यिक भूखण्ड	119	आवासीय/ग्रुप हाउसिंग	68	रे विंग	07	गेटव	03
इसमें/संकेत	139	डॉरल/रेस्टरेक्ट	13	पेट्रोल पम्प/फ्यूल डिनिंग स्टेशन	07	क्लब	07	संस्थानिक	10	कियोक	05

13	आबू रोड	07	चूरू	05	नागौर	07	उदयपुर
15	अजमेर	10	बीकानेर	19	पाली	21	जयपुर (उत्तर)
23	अलवर	09	झुंझरू	18	झालावाड़	02	जयपुर (दक्षिण)
13	भिवाड़ी-1	20	भरतपुर	28	किशनगढ़	08	जयपुर (श्रीमती)
13	भिवाड़ी-1A	20	किशनगढ़	19	राजसमंद	12	ईपीआईसी सीमापुर, जयपुर
15	धिलोठ	30	भीलवाड़ा	10	कोटा	09	जोधपुर
04	दौसा	22	नीमराना	08	सीकर	07	श्रीगंगानगर
01	बालोतरा			10	बोरानाडा	13	सवाईमाधोपुर

***25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान**

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कैन, जयपुर-302005
ई-नीलामी हेल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, हार्दत्तएचए +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in
आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तों, ईएमपी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें <https://riico.rajasthan.gov.in> या <https://www.riico.co.in>

मुख्यमंत्री ने जनपथ पर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई

उन्होंने आम जवान ज्योति पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वालों को सम्मानित किया

जयपुर, 13 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के जनपथ-स्थित अमर जवान ज्योति पर आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया तथा उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा जन-जागृति रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों को हैलमेट वितरण किये।

ये सभी वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आमजन को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करेंगे। शर्मा ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों को हैलमेट वितरण किया तथा व्यवसायिक वाहनों पर

रिफ्लेक्टिव टेप लगाई।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा का संदेश देने वाले गुब्बारे हवा में छोड़े। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, सांसद मंजू शर्मा,

विधायक डॉ. गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, विभिन्न विभागों के बड़े अफसर, बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राएँ एवं आमजन उपस्थित थे।

वाले नागरिकों को सम्मानित किया। शर्मा ने इन जीवन रक्षकों का हाँसला बढ़ाते हुए उनके नेक कार्य की सराहना की। सम्मानित होने वालों में संदीप गुप्ता, नितेश यादव, सुनील सिरवी, संजय कुमार एवं सुरता देवी शामिल रहे। शर्मा ने कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जन-जागृति रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 500 ऑटो रिक्शाओं को भी फ्लैग ऑफ किया।

कांग्रेस की “वोट चोर गद्दी छोड़” महारैली आज

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं

नयी दिल्ली, 13 दिसम्बर। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ चलाए गये अपने अभियान के तहत रविवार 14 अप्रैल को यहाँ रामलीला मैदान में होने वाली “वोट चोर-गद्दी छोड़” महारैली की तैयारी पूरी कर ली है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर बताया कि रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

यादव ने रैली स्थल रामलीला मैदान से जारी संदेश में लोगों से बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा, “मेरी अपील है कि इस रैली में शामिल होकर वोट चोरी

■ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने एक वीडियो जारी कर रैली के आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी व लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की।

के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए।”

इससे पहले कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा “जब वोट चोरी पकड़ी गई तो चोर बौखला गया और अब वो मुद्दों को पटकाने का काम कर रहा है। वोट चोरी से जुड़े हमारे सवाल स्पष्ट हैं,

जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है।

अब 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक विशाल रैली हो रही है। मेरी अपील है कि आप सब भी रैली में आइए, क्योंकि हमें वोट चोरों को भागने नहीं देना है।”

हिट एण्ड एन केस, आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एण्ड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीफ कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसौह की बेंच ने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से हैं और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं। बेंच ने शुक्रवार को कहा, यह शह में मांसिडीज खड़ी करता है, बीएमडब्ल्यू निकालता है, उससे टक्कर मारता है और फरार हो जाता है।

‘मोदी सरकार नाम बदलने में धुरंधर है’

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। कांग्रेस ने सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा का नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि पूरे देश को मालूम है कि नाम बदलने में मोदी सरकार धुरंधर है लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि उसने सिर्फ पंडित जवाहर लाल नेहरू से ही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी नाम से भी नफरत है। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना चल रही थी और लंबे समय से इस योजना के तहत गांवों में लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन अब गांधी शब्द हटाकर सरकार ने योजना का नाम बापू कर दिया है जिससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार को

■ मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा।

गांधी नाम से भी नफरत है। पार्टी संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मनरेगा का नाम बदलने के निर्णय पर कहा, “योजनाओं के नाम, कानून के नाम बदलने में मोदी सरकार धुरंधर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ग्रामीण एलपीजी वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला नाम दिया... पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नाम देने

में ये धुरंधर है।” उन्होंने कहा “हैरानी इस बात की है कि पंडित नेहरू से तो इन्हें नफरत है लेकिन महात्मा गांधी से इतनी नफरत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 से चल रही है... इसका नाम आप पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं, महात्मा गांधी नाम से क्या दिक्कत है...”

पंकज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पीयूष गोयल रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे।

पार्टीशन के आठ दशक ...

■ क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में शांति जमीन की मिलिक्यत के बारे में समझौतों से नहीं, बल्कि उस साहस को स्वीकार करने से आएगी कि दोनों देशों की ऐतिहासिक धरोहर व पृष्ठभूमि में काफी समानताएं हैं, काफी “ओवर लैपिंग” है।

भारत के क्षेत्रीय दावों को वैधता मिलती है। लेकिन यह कश्मीर को एक हथियारबंद एकल पहचान के बजाय, सदियों में बनी कई परतों वाली सभ्यता के रूप में देखने की बौद्धिक गुंजाइश जरूर खोलता है।

यह अंतर शांति के लिए मायने रखता है। कश्मीर आंशिक रूप से इसलिए भी अनसुलझा रहा है, क्योंकि वह दोनों पक्षों के लिए पहचान का प्रतीक बन चुका है, जहाँ बारीकियों या साझा स्मृतियों के लिए बहुत कम जगह बचती है। सांस्कृतिक कट्टरता राजनीतिक रुख को और कठोर बना देती है। इसके विपरीत, अकादमिक जुड़ाव जटिलता और ऐतिहासिक गहराई लाता

है, वही तत्व, जो सुलह के लिए जरूरी है, लेकिन जिन्हें राजनीति अक्सर दबा देती है।

इसका एक शांत मानवीय पक्ष भी है। जब पाकिस्तानी विद्वान कश्मीर के बौद्धिक इतिहास से जुड़े संस्कृत ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करते हैं, तो कश्मीर के केवल नक्शे की समस्या नहीं रह जाता, बल्कि एक जीती-जागती, विवादित विरासत के रूप में सामने आता है। यह भारतीय पाठकों को भी चुनौती देता है कि वे ऐसे प्रयासों को खतरा या समझौते के रूप में नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत स्वाभिवल के दायरे के रूप में देखें। ऐसे समय में जब कश्मीर पर औपचारिक बातचीत रुकी हुई है और

भरोसा बढ़ाने के उपाय लगभग नहीं के बराबर हैं, इस तरह की पहलें इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये राज्य की औपचारिक राजनीति से नीचे के स्तर पर काम करती हैं। ये न तो सीमाएँ बदलती हैं और न ही विवाद सुलझाते हैं, लेकिन वे उस सभ्यतागत कठोरता को ढीला करती हैं, जो इन विवादों को स्थायी रूप से जमाए रखती हैं। इस मायने में, लाहौर की संस्कृत की क्लास सिर्फ अतीत से जुड़ी बात नहीं है। यह एक गहरी आधुनिक धारणा का होना चाहिए। एक साझा बौद्धिक विरासत को फिर से खोलकर, संस्कृत के साथ पाकिस्तान का यह जुड़ाव एक मामूली, लेकिन शक्तिशाली याद दिलाता है कि दक्षिण एशिया में शांति की शुरुआत शादद जमीन के समझौतों से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के मिले-जुले इतिहास को स्वीकार करने के साहस से हो सकती है।

‘बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई स्वागत योग्य’

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

■ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया व कहा, भाजपा पहले इसका विरोध करती थी।

की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह अनुमति भाजपा के नेतृत्व वाली उसी सरकार ने दी है जो पहले एफडीआई का विरोध करती आ रही है।

चिदम्बरम ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा “मैं बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ। मुझे गुजराल सरकार का वह दिन याद है जब भाजपा ने संसद में उस विधेयक का विरोध किया था जिसमें बीमा क्षेत्र में 20 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। यह एक लंबी दूरी है जिसे हमने 1997-98 से तय किया है।”

आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि शिवकुमार वर्तमान सत्र के समाप्त होते ही मुख्यमंत्री सिद्धार्थपैया की जगह ले लेंगे।

दिल्ली में वायु प्रदूषण में भारी तेजी

ग्रेप-3 नियम लागू करने के कुछ ही घंटों में ग्रेप-4 नियम लागू किए गए

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण तेजी से बढ़ने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को सुबह ग्रेप-3 लागू किया और शाम होते-होते ग्रेप-4 लागू करने की स्थिति बन गयी। ग्रेप, यानी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चार चरण हैं जिनके तहत प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी अलग-अलग उपायों को लागू किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की है।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार तक ग्रेप-2 लागू था। आयोग ने शनिवार सुबह ग्रेप-3 लागू करने का फैसला किया जिसमें और कई प्रतिबंधों तथा अधिक उपायों का प्रावधान है। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद तेजी से बढ़ते

स्टेट जीएसटी ने 200 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी

विभाग ने प्रदेश भर में 170 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ सर्वे कर यह उपलब्धि हासिल की

जयपुर, 13 दिसंबर। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कर चोरी के विरुद्ध ज़ोरों टॉलरेंस नीति तथा स्वच्छ कर प्रशासन की मंशा के अनुरूप, राज्य के वाणिज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी) द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। विभाग ने प्रदेश भर में एक साथ 110 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सर्वे कार्यवाही करते हुए लगभग 200 करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा किया है।

यह कार्यवाही विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गोतम के निर्देश पर की गई। अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए वाणिज्य कर विभाग के 300 से अधिक अधिकारियों को शामिल करते हुए अलग-अलग टीमों गठित की गईं, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ यह कार्यवाही की। विभाग को लंबे समय से सूचनाएं

■ विभाग को लंबे समय से प्रदेश में प्लाईवुड, सैनेटरी आइटम, लोहा स्क्रैप, टाइल्स, खाद्य तेल, होटल, कपास, टिम्बर व रियल एस्टेट आदि सेक्टर में कर चोरी की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं।

प्राप्त हो रही थीं कि प्रदेश में प्लाईवुड, सैनेटरी आइटम, लोहा स्क्रैप, टाइल्स, खाद्य तेल, होटल, कपास, टिम्बर, रियल एस्टेट सहित, कई सेक्टर में कुछ व्यापारी कर चोरी में संलिप्त हैं। इन्हें सूचनाओं के आधार पर यह व्यापक अभियान चलाया गया।

प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न सेक्टर में एक साथ कार्यवाही की गई है, जिससे कर चोरी में लिप्त व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान, कई स्थानों से कच्ची परिचियां, फर्जी बिलिंग एवं अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए

हैं। सर्वे कार्यवाही के दौरान ही कई व्यापारियों ने कर चोरी स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि विभाग में जमा करवाई है। विभाग द्वारा जब दस्तावेजों के आधार पर अब विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे आगे और भी बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में कर चोरी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्यवाहियों में और अधिक तेजी लाई जाएगी।

‘मोदी तन्खाह के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुरक्षा से संबंधित होता है और इसे श्रम कानून के तहत प्रबंधकीय पर्यवेक्षण से नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि एक नियामक ढांचे में प्रयुक्त कानूनी शब्दों को दूरस्थ नियामक ढांचे में स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जिनका उद्देश्य और संदर्भ अलग होता है।

बकाया वेतन के मामले में, कोर्ट ने औद्योगिक ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पायलटों की बर्खास्तगी अवैध थी और बिना उचित प्रक्रिया के की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को लागू करते हुए, खंडपीठ ने यह दोहराया कि गलत बर्खास्तगी के मामलों में सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन के साथ पुनर्निश्चित सामान्य नियम है, विशेष रूप से जब नियोजता यह साबित करने में असमर्थ हो कि कर्मचारी अन्यत्र लाभकारी रूप से कार्यरत था।

संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। संसद पर वर्ष 2001 में आज ही के दिन किये गये आतंकवादी हमले की 24 वीं बरसी पर शनिवार को यहां देश के शीर्ष नेतृत्व ने इस हमले का मुकाबला करते हुए प्राण न्योछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन परिसर में शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अनेक केन्द्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राधाकृष्णन ने अपने संदेश में कहा, “मैं देश के साथ मिलकर उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारी संसद की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका अदृष्ट साहस और सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने के हमारे राष्ट्र के संकल्प की एक स्थायी याद दिलाता है।”

मोदी ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के शौर्य को स्मरण करते हुए कहा, “आज के दिन हमारा देश 2001 में संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को याद करता है।

भारत पर लगे टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव पेश

■ तीन सदस्यों ने कांग्रेस के निचले सदन, “हाउस ऑफ रैप्रेजेंटेटिव” में प्रस्ताव पेश किया

■ प्रस्ताव डेबोरा रॉस, मार्क वेसी व राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया और ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बताया।

जोवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के ज़रिए भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सेक्टर में हज़ारों नौकरियाँ पैदा हुई हैं, जबकि उत्तर कैरोलिना के कारोबारी हर साल भारत को हज़ारों डॉलर का सामान

मुहैया कराते हैं। वेसी ने कहा, “भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और ये अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के लोगों पर एक रोज़गार का कर हैं जो पहले से ही बढ़ती कीमती से जूझ रहे हैं।” भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने टैरिफ को नुकसानदायक

‘ग्राम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि पंचायती राज विभाग ने गत 10 जनवरी को पंचायती राज अधिनियम की धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्संयोजन, नवसृजन और पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांगे थे। राज्य सरकार ने धौलपुर व करौली जिला कलेक्टर की ओर से भेजे गये प्रस्तावों को नहीं मानते हुए, गत 20 नवंबर को मनमाने तरीके से संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय बदल दिए। इसके अलावा, करौली जिले से जुड़े मामले में पंचायत मुख्यालय करीब 14 किलोमीटर दूर कर दिया, जबकि नियमानुसार यह दूरी अधिकतम पांच किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। याचिकाओं में कहा गया कि इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पहले से ही केंद्र को इस योजना को फिर से शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय नियमों से वंचित कर रहा है। अभी तक, केंद्र सरकार ने पंचायतों को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा था। मनरेगा को बदलते हुए, केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना